

असली आज़ादी

The Voice of Union Territory Dadra and Nagar Haveli and Daman-Diu Since 2005

www.asliazadi.com

■ वर्ष: 21, अंक: 88 ■ दमण, शनिवार 20 दिसंबर 2025 ■ पृष्ठ: 8 ■ मूल्य: 2 रु ■ RNINO-DDHIN/2005/16215 ■ संपादक- विजय जगदीशचंद्र भट्ट

दमण में हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया दमण-दीव का 65वां मुक्ति दिवस



■ दमण समाहर्ता सौरभ मिश्रा ने किया ध्वजारोहण ■ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में तथा माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेल जी की दूरदर्शी सोच और कुशल मार्गदर्शन के कारण संघ प्रदेश दमण ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं : समाहर्ता सौरभ मिश्रा



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। दमण में आज दमण-दीव का 65वां मुक्ति दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ समाहर्तालय परिसर में मनाया गया।

इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दमण जिला समाहर्ता सौरभ मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। समाहर्ता में जनप्रतिनिधियों, अधिकारीगण, स्थानीय नागरिक,

शिक्षक और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के पश्चात समाहर्ता सौरभ मिश्रा ने अपने संबोधन में विगत कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जी के आशीर्वाद से तथा संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेल जी के कुशल नेतृत्व में दमण जिले में हुए विकास कार्यों पर संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन वर्षों में प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और स्वच्छता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ पूरी की गई हैं। समाहर्ता सौरभ मिश्रा ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जी के सक्षम नेतृत्व में तथा माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेल जी की दूरदर्शी सोच और कुशल मार्गदर्शन के कारण संघ प्रदेश दमण ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का है और इसके लिए हम अनवरत प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में समाहर्ता ने सभी नागरिकों से दमण के विकास में सहयोग करने का आग्रह किया और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके प्रयासों से यह दिन संभव हुआ। गौरतलब है कि दमण-दीव के 65वें मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में दमण नगरपालिका, जिला पंचायत, सभी पंचायतों तथा सभी विद्यालयों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

दीव में मनाया गया दमण-दीव का 65वां मुक्ति दिवस: समाहर्ता राहुल देव बूरा ने फहराया तिरंगा

■ माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेल के सक्षम, अनुभवी एवं कुशल मार्गदर्शन में दीव प्रशासन द्वारा प्रदेश में तेजी से अनेकानेक परियोजनाओं को लागू किया गया है और कई विकास कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जा रहा है : समाहर्ता राहुल देव बूरा



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दीव 19 दिसंबर। दमण-दीव प्रशासन के दीव जिला में दमण-दीव का 65वां मुक्ति दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दीव समाहर्ता राहुल देव बूरा ने म्युनिसिपल गार्डन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह के आरम्भ में समाहर्ता राहुल देव बूरा ने मुक्ति दिलाने वाले वीर सपूतों और वीरगणों को पुष्पहार चढाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी उपस्थितों का

अभिवादन करते हुए और उन्हें 65वें मुक्ति दिवस की बधाई देते हुए अपने उद्बोधन में समाहर्ता ने कहा कि यह मुक्ति दिवस उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं सैनिकों के महान प्रयासों और बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने मुक्ति संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे दी और इस प्रदेश को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। दीव के तीव्र विकास की चर्चा करते हुए समाहर्ता राहुल देव बूरा ने कहा कि हम सभी इस बात के

साक्षी हैं कि पिछले 10 वर्षों में दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेल के अनुभवी एवं कुशल मार्गदर्शन में इस प्रदेश का हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। माननीय प्रशासक के सक्षम, अनुभवी एवं कुशल मार्गदर्शन में दीव प्रशासन द्वारा प्रदेश में तेजी से अनेकानेक परियोजनाओं को लागू किया गया है और कई विकास कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जा रहा है। (समाचार का शेष पेज 3 पर)

दमण-दीव के 65वें मुक्ति दिवस पर नानी दमण भाजपा कार्यालय पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेश आगरिया ने किया ध्वजारोहण



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। दमण-दीव के 65वें मुक्ति दिवस पर आज नानी दमण स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेश आगरिया ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री जिग्नेश पटेल एवं सुनील पाटिल, दमण जिला भाजपा अध्यक्ष भरत पटेल, दमण जिला पंचायत अध्यक्ष धरम पटेल, दमण नगरपालिका अध्यक्ष दीपिका टंडेल, सिलवासा ग्रामीण जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रधान, सिलवासा नगरपालिका अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, दादरा नगर हवेली

जिला पंचायत अध्यक्ष निशा भावर और दमण शहर भाजपा के अध्यक्ष पीयूष पटेल, दमण-दीव के पूर्व सांसद लालू पटेल, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल, प्रदेश एवं जिला के विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारियों एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश आगरिया ने कहा कि 19 दिसंबर का यह पावन दिन दमण-दीव के गौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। आज से 65 वर्ष पूर्व हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के

संघर्ष, बलिदान और हृदय संकल्प के परिणाम स्वरूप दमण-दीव ने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्ति पाई थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं समस्त दमण-दीव वासियों को 65वें मुक्ति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई देता हूँ। यह दिन हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सशक्त करने का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं पूर्ण मार्गदर्शन में तथा यहां के यशस्वी प्रशासक श्री प्रफुलभाई पटेल जी के नेतृत्व में दमण-दीव ने विकास, सुशासन

और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। भाजपा का संकल्प है कि सेवा, समर्पण और अंत्योदय के मंत्र के साथ अंतिम पॉइंट में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाया जाए। इस मुक्ति दिवस पर हम सब मिलकर दमण-दीव को प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लें। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय स्वराज चुनावों में लगातार विजयी होने वाले जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। जिसमें शंकरभाई पटेल, तमन्ना खोजा, सविता पटेल का सम्मान किया गया। दमण जिला की महिला

सरपंच सहित पूरी महिला पंचायत घेलवाड़ दूसरी बार लगातार निर्विरोध निर्वाचित होने पर घेलवाड़ सरपंच हिताक्षी पटेल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विविध क्षेत्रों में प्रदेश का नाम उज्ज्वल करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों, योग को प्रोत्साहित करने वाली छात्रा एवं भारत की सनातन संस्कृति को धार्मिक पैदल यात्रा के माध्यम से सम्मानित करने वाले, दमण से केदारनाथ तक पैदल यात्रा करने वाले युवा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन माजिद लाधानी एवं आभार विधि फाल्गुनी पटेल ने किया।

प्रशासक प्रफुल पटेल को भविष्य में आधुनिक दमण के शिल्पकार के रूप में सदैव याद किया जाएगा: जिग्नेश जोगी



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। दमण के सार्वजनिक विद्यालय में दमण-दीव का 65वां मुक्ति दिवस अत्यंत हर्षोल्लास, देशभक्ति और गौरव के साथ मनाया गया। इस गौरवशाली अवसर पर विद्यालय परिवार ने उन ऐतिहासिक क्षणों को भावपूर्ण स्मरण के साथ याद किया जब 19 दिसंबर, 1961 को भारतीय सेना के 'ऑपरेशन विजय' के माध्यम से गोवा, दादरा-नगर

हवेली तथा दमण-दीव को पुर्तगाली दासता से मुक्त कराकर भारत के अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया गया था। वर्षों की गुलामी के पश्चात इस दिन दमण ने स्वतंत्रता के नए सूर्योदय का अनुभव किया। यह गरिमामयी समारोह विद्यालय कमेटी के सदस्य जयंती दाजी टंडेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। इस अवसर पर विद्यालय

के पूर्व अध्यक्ष जोगीभाई टंडेल, वर्तमान अध्यक्ष जिग्नेश जोगी, सेक्रेटरी रुद्रेश टंडेल, कोषाध्यक्ष दिलीप गोएला, सोनियर सेक्रेटरी प्रिंसिपल दीपक मिश्री, वाइस प्रिंसिपल बी. डी. जगताप, सेक्रेटरी प्रिंसिपल शीतल पटेल तथा शाईनिंग स्टार स्कूल की प्रिंसिपल वैशाली टंडेल सहित स्कूल स्टाफ एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं (समाचार का शेष पेज 3 पर)

दमण जिला पंचायत कार्यालय पर मनाया गया 65वां मुक्ति दिवस: जिला पंचायत अध्यक्ष धरम पटेल ने किया ध्वजवंदन

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। दमण जिला पंचायत अध्यक्ष धरम पटेल ने दमण-दीव के 65वें मुक्ति दिवस पर आज जिला पंचायत कार्यालय के प्रांगण में ध्वजवंदन किया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों को दमण-दीव के आजादी पर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने दमण-दीव को पुर्तगाली हुकूमत से आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने दमण-दीव की आजादी की लड़ाई ऑपरेशन विजय पर भी प्रकाश



डाला। प्रशासक प्रफुल पटेल की अगुवाई में दानह एवं दमण-दीव में हो रहे विकास कार्यों को अभूतपूर्व बताते हुए उसकी प्रशंसा की। उनका कहना था कि प्रशासक प्रफुल पटेल जी के कुशल नेतृत्व

में संघ प्रदेश श्रीडी के सभी क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। आने वाले दिनों में संघ प्रदेश के विकास की तस्वीर और अधिक बुलंद होगी। उन्होंने संघ प्रदेश प्रशासन के सहयोग से दमण जिला के सभी

ग्राम पंचायतों का समान विकास करने का भरोसा दिलाया। इसके पहले दमण जिला पंचायत अध्यक्ष धरम पटेल ने तिरंगा फहराया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर जिला पंचायत उपप्रमुख

रीना पटेल, जिला पंचायत सदस्यों, सरपंचों, सीईओ, बीडीओ, एजुकेशन ऑफिसर तथा जिला पंचायत और बीडीओ स्टाफ एवं नागरिकों और विद्यार्थियों की मौजूदगी रही।



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। दमण-दीव के 65वें मुक्ति दिवस के पावन अवसर पर दमण नगरपालिका प्रांगण में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर

पर दमण नगरपालिका की अध्यक्ष दीपिका टंडेल के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित नगरपालिका के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर

उपस्थित छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। अपने संदेश में दमण नगरपालिका अध्यक्ष दीपिका टंडेल ने मुक्ति (समाचार का शेष पेज 3 पर)

हरियाणा में वंदे मातरम पर चर्चा से लेकर मुख्यमंत्री और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक

गुरग्राम (एजेंसी)। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन काफ़ी हंगामेदार रहा। सदन में वंदे मातरम पर चर्चा से लेकर मुख्यमंत्री और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सत्र के दौरान विधायक घनश्याम ने वंदे मातरम पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस विधायक ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर कहा कि पहाड़ों को उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधकर कहा कि आपने विभाजन के समय वंदे मातरम को काट दिया था। इस बयान के बाद सदन में जमकर नारेबाजी हुई और स्पीकर हरविंद कल्याण को सदन की कार्यवाही 30 मिनट (लंच तक) के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी ने कांग्रेस द्वारा लाए अविश्वास प्रस्ताव पर चुटकी ली। उन्होंने ध्यान दिलाया कि नौटिस पर विपक्ष के नेता (भूपेंद्र सिंह हुड्डा) के हस्ताक्षर नहीं थे। कांग्रेस को हुड्डा पर यकीन नहीं, देश की जनता को कांग्रेस पर नहीं, पर सदन में विपक्ष चाहिए था, हम तो हुड्डा साहब ही चाहते थे, चाहे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहे या न चाहे। हुड्डा साहब ही सही इस बयान के बाद कांग्रेस विधायक वेल में आ गए और जोरदार हंगामा किया। हंगामे के दौरान जब मंत्री विज बोलांना चाहते थे, तब स्पीकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर विज नाराज हो गए और स्पीकर से ही भिड़ गए। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा है।

दिल्ली से कई एयरलाइन की 27 उड़ानें और इंडिगो की 59 घरेलू उड़ानें रद्द

नई दिल्ली (एजेंसी)। घने कोहरे और उसकी वजह से दृश्यता कम होने के कारण गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर कई एयरलाइन की 27 उड़ानें रद्द कर दी गईं और कई के परिचालन में देरी हुई। आधिकारिक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बीच इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक उसने अपने घरेलू नेटवर्क में 59 उड़ानें रद्द कर दी हैं। सूत्र ने बताया कि घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 16 प्रस्थान और 11 आगमन से जुड़ी अब तक 27 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। यात्रियों के लिए जारी एक परामर्श में डखल ने कहा कि घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन वर्तमान में फैंट (श्रेणी)-तीन की स्थितियों के अंतर्गत आता है। इस तरह की परिस्थितियों में परिचालन में देरी या व्यवधान हो सकता है। इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक एयरलाइन ने गुरुवार को 59 उड़ानें रद्द की थीं और शुक्रवार के लिए 28 और उड़ानें रद्द कीं। हालांकि, इंडिगो ने इसका कोई कारण नहीं बताया।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने की एक और गिरफ्तारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में 16 दिसंबर को एक और गिरफ्तारी की है। ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि गिरफ्तार सीध्या चौरियाया को रायपुर की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया जहां से उसे तीन दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एसबीडी-ईओइएल्यू द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी पर जांच शुरू की है। पुलिस की जांच से पता चला कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराधों के माध्यम से लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय उत्पन्न हुई। ईडी की जांच में पता चला कि सीध्या को लगभग 115.5 करोड़ रुपये की रिश्तत प्राप्त हुई थी। ईडी की जांच में डिजिटल रिकॉर्ड, जल सामग्री और लिखित बयानों के रूप में जुटाए गए सबूतों से यह साबित हुआ कि सीध्या शराब गिराहों की सख्ती सहयोगी थी। डिजिटल साक्ष्य से पुष्टि हुई कि वह अनिल टूटेजा और वैतन्य बघेल सहित शराब गिराहों के प्रमुख सदस्यों के बीच केंद्रीय समन्वयकर्ता एवं मध्यस्थ की भूमिका निभा रही थी तथा अवैध धन के सृजन एवं धनशोधन में सुविधा प्रदान कर रही थी। बरामद वेट से यह भी पता चला कि वह गिराहों के प्रारंभिक संगठन में शामिल थी जिसमें अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास को आबकारी विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने में सहायता करना भी शामिल था। इससे पहले ईडी ने संबंधित मामले में अनिल टूटेजा (पूर्व आईएफएस); अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्ले, अनवर देबर, अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस), कवासी लखमा (छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री) और वैतन्य बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र) को गिरफ्तार किया गया है।

मध्य प्रदेश के साई भत्तों ने साई बाबा के चरणों में 20 लाख रुपये का सोने का मुकुट चढ़ाया



शिर्डी (एजेंसी)। देश और विदेश के करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का स्थान शिरडी की साई बाबा में अटूट आस्था है। साई बाबा के चरणों में भक्त अपना आभार जताने के लिए अलग-अलग तरह के दान करते हैं। इसी भावना के साथ, मध्य प्रदेश के हरदासपुर के एक साई भक्त तेज बहादुर सिंह ने साई बाबा के चरणों में 20 लाख रुपये का सोने का मुकुट चढ़ाया है। मध्य प्रदेश के हरदासपुर के रहने वाले तेज बहादुर सिंह 2002 से शिरडी साई बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। पिछले 24 सालों से साई बाबा में उनकी अटूट आस्था है। तेज बहादुर सिंह ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में साई बाबा से जो कुछ भी मांगा, वह सब मुझे मिला। 124 साल बाद, साई बाबा की कृपा से मुझे एक बेटा हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बड़ी मुश्किलों का सामना किया। हालांकि, साई बाबा ने मुझे हमेशा उन मुश्किलों से बाहर निकाला। तेज बहादुर सिंह, जो पहले बहुत मुश्किल हालात में रहे थे, ने कहा है कि आज उन्हें जो भी कामयाबी, खुशी, खुशहाली और सुकून मिला है, वह सब साई बाबा की कृपा से है। तेज बहादुर सिंह ने कहा, आज मेरे पास जो कुछ भी है, वह साई बाबा की कृपा से है। इसलिए मुझे साई बाबा को कुछ देना है। इसी भावना से मैंने यह सोने का मुकुट चढ़ाया है। दरअसल साई भक्त तेज बहादुर सिंह ने श्रद्धा के साथ साई बाबा के चरणों में करीब 200 ग्राम वजन का एक आकर्मिक और खुबसूरती से सजा हुआ सोने का मुकुट चढ़ाया। इस कलात्मक सोने के मुकुट की कीमत करीब 20 लाख 16 हजार रुपये है। साई बाबा के चरणों में सोने का मुकुट चढ़ाने के बाद, इसे साई बाबा संस्थान के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडो को सौंप दिया गया। इस मौके पर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडो ने दरियादिल साई भक्त तेज बहादुर सिंह को सम्मानित किया और उनकी आस्था और योगदान के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया।

यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग भविष्य के लिये तैयार सिविल सेवाओं के निर्माण की कुंजी हैं: राष्ट्रपति

हैदराबाद (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को भारत के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए सिविल सेवा भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और तकनीकी तैयारी पर अधिक जोर देने का आह्वान किया।

राष्ट्रपति ने यहां रामोजी फिल्म सिटी में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि एक ऐसे संघ में भाग लेना सौभाग्य की बात है जो देश भर से यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों के प्रमुखों को एक साथ लाता है।

राष्ट्रपति ने भारत में लोक सेवा आयोगों के लंबे और प्रतिष्ठित इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना एक अक्टूबर, 1926 को हुई थी और बाद में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया। 26 जनवरी, 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद, संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों ने अपनी वर्तमान संवैधानिक भूमिकाएँ ग्रहण कीं।

केंद्रीय और राज्य लोक सेवा आयोगों के



योगदान का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवा आयोगों ने सरकारी प्रशासन में समानता, निष्पक्षता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन संस्थानों के माध्यम से चयनित सिविल सेवाएँ भारत के आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता और प्रशासन के लिए बहुत अहम रही हैं, जिससे संघ लोक सेवा आयोग देश के सबसे भरोसेमंद संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है।

श्रीमती मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि कौशल की कमी को प्रशिक्षण के माध्यम से दूर किया जा सकता है, लेकिन सत्यनिष्ठा की कमी ऐसी चुनौतियाँ पैदा करती हैं जिन पर काबू पाना मुश्किल है तो ऐसे में भर्ती में ईमानदारी और

सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोगों को उम्मीदवारों के बीच नैतिक अभिविन्यास और संवेदनशीलता का आकलन करने के लिए बेहतर प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रह रहे और कमजोर वर्गों के प्रति। राष्ट्रपति ने भविष्य की चुनौतियों पर जोर देते हुए लोक सेवा आयोगों से उभरते तकनीकी मुद्दों का अनुमान लगाने, पारदर्शिता को मजबूत करने और भर्ती प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सर्वोत्तम विधियों, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी अपनाने, कानूनी ढांचे और प्रक्रिया सुधारों को साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण

मंच प्रदान करता है। उन्होंने भारत के तेजी से आर्थिक विकास और आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की उसकी महत्वाकांक्षा का जिक्र करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग भविष्य के लिए तैयार ऐसी सिविल सेवा का पोषण करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देना जारी रखेंगे जो स्थिरता को रचनात्मकता के साथ और निरंतरता को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ती हैं। श्रीमती मुर्मू ने संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों को उनके प्रयासों में लगातार सफलता मिलने की शुभकामनाएँ दीं।

सीएम ममता ने ‘कर्मश्री’ योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़ा राजनीतिक और वैचारिक बयान देते हुए राज्य सरकार की रोजगार योजना कर्मश्री का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की।



उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर शर्म महसूस होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के नाम को कल्याणकारी योजनाओं से हटाया जा रहा है। ममता बनर्जी का इशारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के नाम में किए गए कथित बदलावों के ओर था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘कर्मश्री’ योजना के तहत राज्य में 75 से 100 दिनों तक रोजगार दिया जाता है और अब यह योजना महात्मा गांधी के नाम से जानी जाएगी। ममता बनर्जी ने भावुक अंदाज़ में कहा, मैं वास्तव में शर्मिदा हूं। राष्ट्रपिता का नाम योजनाओं से हटाया जा रहा है। मैं किसी और को दोष नहीं देती, क्योंकि मैं इसी देश की नागरिक हूं। हम राष्ट्रपिता को भूलते जा रहे हैं, यह दुखद है। उन्होंने केंद्र सरकार

पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि अगर केंद्र महात्मा गांधी को सम्मान नहीं देगा तो बंगाल देगा। ममता ने कहा, अगर आप महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करेंगे, तो हम करेंगे। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने महात्मा गांधी के साथ-साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर, डॉ. भीमराव आंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और लाला-लाल-पाल का भी उल्लेख किया। उन्होंने बंगाल की समावेशी संस्कृति की बात करते हुए कहा कि राज्य हर समुदाय और हर विचारधारा का सम्मान करता है। देखा जाये तो यह बयान ऐसे समय आया है जब मनरेगा के नाम और पहचान को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस चल रही है और तृणमूल कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की इतिहास और प्रतीकों को बदलने की राजनीति बता रही है।

वायु प्रदूषण पर चर्चा से भागी सरकार... ये शीतकालीन नहीं, बल्कि प्रदूषण सत्र

–कांग्रेस महाराष्ट्रचिव जयराम रमेश का केंद्र पर आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला कर आरोप लगाया कि हाल ही में समाप्त हुआ संसद का शीतकालीन सत्र सरकार की इस मुद्दे पर बहस करने की अनिच्छा के कारण प्रभावी रूप से प्रदूषण सत्र में बदल गया। प्रेसवार्ता को संबोधित कर कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि संसद में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया से उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसमें उन्होंने प्रदूषण और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के बीच किसी भी संबंध से इंकार किया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह शीतकालीन सत्र नहीं, बल्कि प्रदूषण सत्र था। मैं तब सब्सब्द रह गया जब सरकार ने गुरुवार को संसद में यह जवाब दिया कि प्रदूषण और फेफड़ों की समस्याओं के बीच कोई संबंध नहीं है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, जहां प्रदूषण का स्तर हफ्तों से गंभीर बना हुआ है, बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर विस्तृत चर्चा की बार-बार मांग की थी।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण



पर चर्चा की मांग की थी। हम लोकसभा और राज्यसभा में वायु प्रदूषण पर बहस चाहते थे। कांग्रेस नेता ने केंद्र के उस दावे को खारिज किया कि विपक्ष द्वारा व्यवधान डालने से प्रदूषण पर बहस नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि विपक्ष की मांगों के बावजूद लोकसभा को इस मुद्दे पर चर्चा किए बिना अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। दुर्भाग्य से, लोकसभा में ही सत्र को गुणवत्ता पर विस्तृत चर्चा की बार-बार मांग की गई।

केंद्र के आरोपों पर कांग्रेस नेता रमेश ने कहा

कि चर्चा न होने की जिम्मेदारी सरकार की है। राज्यसभा में वायु प्रदूषण पर बहस चाहते थे। ‘सरकार का यह बयान कि कांग्रेस के कारण प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी, गलत है। मैं इस बयान को पूरी तरह से खारिज करता हूं। रमेश की ये टिप्पणी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा कांग्रेस पर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वायु प्रदूषण पर प्रस्तावित चर्चा को बाधित करने का आरोप लगाने के बाद आई है। रिजिजू ने दावा किया था कि सरकार पूरे दिन की बहस के लिए तैयार थी, लेकिन विश्वश्व के व्यवधान के कारण ऐसा करने से रोक दिया गया।

दूसरे धर्म में लड़की ने की शादी पिता ने किया संपत्ति से बेदखल, कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को लेकर एक अहम फैसला दिया है। उसने टेस्टेटर की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए एक पिता की वसीयत को वैध ठहराया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी शैला जोसेफ को समुदाय से बाहर के लड़के से शादी करने के कारण संपत्ति से वंचित कर दिया था। यह मामला लैंगिक समानता के कई ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद वसीयत की स्वतंत्रता को अहमियत देता है। जस्टिस अहमनुद्दीन

अमानुल्लाह और जस्टिस चंद्रन ने कहा कि वसीयत स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले रद्द किए जाते हैं। शैला जोसेफ का अपने पिता की संपत्ति पर कोई दावा नहीं है, क्योंकि वसीयत से यह संपत्ति अन्य भाई-बहनों को सौंप दी गई है।

कोर्ट में शैला की ओर से सीनियर एडवोकेट पीवी कृष्णन ने तर्क दिया कि उनकी क्लॉटर्ड को कम से कम 1/9

हिस्सा मिलना चाहिए, जो संपत्ति का नगण्य हिस्सा है, लेकिन बेंच ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के बंटवारे में व्यक्ति की इच्छा के मामले में समानता का सवाल उठता ही नहीं। हम इंक्विटी पर नहीं हैं। टेस्टेटर की इच्छा सर्वोपरि है। उसकी ऑफिस वसीयत से विचलन या उसे निरस्त नहीं किया जा सकता।

बेंच ने टिप्पणी की कि बंचित करने की वजह बताई गई है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता हमारे लिए संपादनी का नियम नहीं तय करती। हम टेस्टेटर

की जगह खुद को नहीं रख सकते। हम अपनी राय थोप नहीं सकते, उनकी इच्छा उनकी अपनी वजहों से प्रेरित है। फैसले में सिविल अपीलों को मंजूर करते हुए शैला की पार्टिशन सूट को खारिज कर दिया। मामला केरल का है, जहां श्रीधरन की मौत के बाद 1990 में भाई-बहनों ने इंजेक्शन सूट दाखिल किया था और वसीयत की कॉपी पेश की थी। शैला ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसे कोर्ट ने बाद में उनके खिलाफ



–हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश किया रद्द

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद में सवाल पछुने के बदले नकदी लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भारत के लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। अदालत के इस फैसले को मोइत्रा के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस वैजनाथ क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरिश चैदामाथन शंकर शामिल थे, ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनिश्चित रख लिया था। महुआ मोइत्रा ने लोकपाल के 12 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ जांच और आगे की कार्रवाई की अनुमति दी गई थी। सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की



ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने दलील दी कि लोकपाल ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उनका कहना था कि अधिनियम की धारा 20(7) के तहत लोकपाल को किसी भी लोकसेवक के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसका पक्ष जानना अनिवार्य है। हालांकि महुआ मोइत्रा से लिखित जवाब मांगा गया था, लेकिन उनके अनुसार लोकपाल ने उनके जवाबों पर समुचित विचार किए बिना ही सीबीआई को आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी।

मामले की पृष्ठभूमि में आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने कारोबारी दर्शन

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

भाजपा सांसद का यह भी दावा था कि महुआ मोइत्रा द्वारा पूछे गए 61 सवालों में से करीब 50 सवाल सीधे तौर पर हीरानंदानी समूह को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से थे। दूसरी ओर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एक्सी राजू ने लोकपाल के आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि आरोपों को मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है और महुआ मोइत्रा को लिखित टिप्पणी देने का पुरा अवसर दिया गया था। हाईकोर्ट के ताना फैसेले से फिलहाल महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई पर विराम लग गया है।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

भाजपा सांसद का यह भी दावा था कि महुआ मोइत्रा द्वारा पूछे गए 61 सवालों में से करीब 50 सवाल सीधे तौर पर हीरानंदानी समूह को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से थे। दूसरी ओर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एक्सी राजू ने लोकपाल के आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि आरोपों को मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है और महुआ मोइत्रा को लिखित टिप्पणी देने का पुरा अवसर दिया गया था। हाईकोर्ट के ताना फैसेले से फिलहाल महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई पर विराम लग गया है।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सब

भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8 प्रतिशत बढ़कर 17.04 लाख करोड़ हो गया

नई दिल्ली ।

भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अब तक (17 दिसंबर) 8 प्रतिशत बढ़कर 17.04 लाख करोड़ हो गया है। इसकी जानकारी केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को दी गई। आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार का कुल सकल कर संग्रह इस साल एक अप्रैल से लेकर 17 दिसंबर तक 20.01 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसमें सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

एनसीएलटी के 50 और अपीली न्यायाधिकरण के 2 नए न्यायालय खोलने का रास्ता साफ

-केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी

नई दिल्ली। कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के 50 और अपीली न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के 2 नए न्यायालय खोलने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर प्रवर समिति के साथ साझा की है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने समिति को बताया है कि वह 'आईबीसी प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियम' के तहत नियम बनाएगा, ताकि समयसीमा का पालन होना सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय ने समिति को

चालू वित्त वर्ष में अब तक 2.97 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। इसमें सालाना आधार पर 13.52 प्रतिशत की गिरावट आई है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर में कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 8.17 लाख करोड़ रुपए रही है, जो कि बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.39 लाख करोड़ रुपए था। इसमें नॉन-कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 8.46 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि एक साल पहले समान अवधि में 7.96 लाख करोड़ रुपए थी। नॉन-कॉरपोरेट टैक्स में व्यक्तिगत

कर और हिंदू अविभाजित परिवारों से वसूलने वाले कर को शामिल किया गया है। समीक्षा अवधि में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) संग्रह 40,194.77 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 40,114.02 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने 25.20 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य रखा है, जो कि सालाना आधार पर 12.7 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ वित्त वर्ष 26 में सरकार को 78,000 करोड़ रुपए का एसटीटी



संग्रह होने का अनुमान है। कर संग्रह में इसतरह का इजाफा देखने को मिला है, जब आम बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर प्रणाली के तहत कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया था। इससे बड़ी संख्या आयकर दाताओं का राहत मिली है।

केवल 3 पद रिक्त थे। मौजूदा आईबीसी ढांचे के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान शुरू करने वाले आवेदन को 14 दिनों के भीतर स्वीकार होना चाहिए, जबकि हकीकत में दिवाला आवेदन स्वीकार करने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों को औसतन एक साल से अधिक लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सदस्यों की कमी और अपेक्षित संख्या न होने के कारण न्यायाधिकरण सप्ताह में केवल कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ही बैठते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यहां तक कि उन न्यायाधिकरणों में, जहां कोई रिक्ति नहीं है, अपेक्षित इच्छा के अभाव के कारण पीठों को रोटेशन के आधार पर कोर्टरूम या हॉल साझा करने के लिए मजबूर होने पड़ता है।

बताया कि 'यह फैसला करने वाले प्राधिकरणों की इंफ्रा, कार्यात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक करने के लिए किया जाएगा। प्रवर समिति ने कहा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने के लिए संबंधित प्रावधानों को सहायक कानूनों के साथ मजबूत करने की जरूरत है। विभिन्न हितधारकों ने समिति को बताया कि न्यायिक क्षमता का विस्तार करने या पीठों की संख्या बढ़ाने और इंफ्रा के सुधार के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाकर न्यायनिर्णय प्रक्रिया के पुनर्गठन की जरूरत है। एनसीएलटी में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल स्वीकृत संख्या 63 है। एनसीएलटी के पीठों में 31 मार्च, 2025 तक

(पेज 8 का शेष समाचार)

सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर....

तथा पात्र प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया गया। अनेक नागरिकों को मौके पर ही प्रमाण-पत्र, योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्रदान किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता की और इसे अत्यंत उपयोगी बताया। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समय और संसाधनों की बचत

होती है तथा समस्याओं के समाधान में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। जिला प्रशासन द्वारा यह भी आवश्यकता कि जिला प्रशासन गाँव की ओर जैसे जनहितकारी कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके।

(पेज 1 का शेष समाचार)

दमण-दीव के 65वें मुक्ति दिवस पर दमण नगरपालिका....

दिवस के अवसर दमण वासियों को शुभकामनाएँ दी और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज हमारा प्रदेश स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले रहा है एवं भारत के मजबूत लोकतंत्र में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह सब उन वीर

जवानों की शहादत की वजह से संभव हुआ है जिन्होंने हमें पुर्तगाली शासन से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। आज के कार्यक्रम में नगरपालिका के चीफ ऑफिसर संजाम सिंह, नगरपालिका के सभी कार्टिसिलरों एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

CHANGE OF NAME

I HAVE CHANGED MY OLD NAME FROM LAKHANI SOHIL KAMRUDIN TO NEW NAME LAKHANI SOHIL KAMRUDINBHAI AS PER MY DOCUMENTS.

विजली बंद होने की सूचना

उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणात्मक विजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क रखरखाव की योजना बनाई गई है। निम्न दर्शित संबंधित सबस्टेशनों से ग्राहकों को मिलने वाली विजली सुबह १०:०० से शाम ६:०० बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी। कृपया तदनुसार आपकी गतिविधियों की योजना बनाएं। हालांकि, विजली आपूर्ति निर्धारित समय से पहले शुरू करने के सभी प्रयास किए जाएंगे।

दिनांक एवं वार	सबस्टेशन	फीडर	क्षेत्र का नाम
२३/१२/२०२५ मंगलवार	खराडपाडा	११ केवी कनाडी-२	प्लुज रिसॉर्ट कनाडी के पास, नवाकुवा रोज़गारी टर्मिन, रोज़गारी गोदाम (नया), कनाडी फाटक आलीशान होटल, टॉपसेल, एम्फाल्ड हिंग कनाडी, खेलसैंट पैकेजिंग कनाडी, कुम्भरवाडी रोड, भील के सामने, पर्ल रिसॉर्ट, कनाडी गांव शेखावटी के पास, बगल में ६६ केवी शेखावटी, मेलियोरा पैकेजिंग प्रा.लि. एलटीडी, पर्ल रिसॉर्ट, प्राई टेक्नी कोरुस प्रा.लि., खाटोर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, राइट सिलेक्शन मार्बल इंडिया, प्रमुख पॉली प्रोडक्ट्स, अमेज़ोन प्लास्टिक्स, सरस्वती पॉलीमर्स, सियाराम पैकेजिंग, विवेक पॉलीप्लास्ट इंडिया, पोलिगोफ-माइक्रो हाइजीन इंडिया, एचएलई ग्लासकोट
२५/१२/२०२५ गुरुवार	रखोली	११ केवी रखोली-२	शीला फोम डीटी, श्रीजी डोर डीटी, वैसाई इन्ड. डीटी, कॉस्मोटेप डीटी, क्रिस्टल ब्लो मॉल्डिंग १ और २ डीटी, ईंजी पैक प्लास्टिक डीटी

विजली चोरी !! जेल की सजा ।
(भारतीय विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा १३५ के तहत)

आपकी सेवा में सदैव उपस्थित

24/7 Helpline 9099991912, 18002395500, 19126, 18002705551

connect.torrentpower.com connect.dnhdd@torrentpower.com

वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर उपस्थित सभी ने वंदे मातरम् को गायकर उसको सम्मानित किया। डीडीए और डीएमए के सभी सदस्यों को दिलीपनगर डेवलपमेंट एसोसिएशन के 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली वर्ष मनाते हुए सभी को मोमेंटो प्रदान किया गया। इस मौके पर डीडीए चेयरमैन लखम टंडेल, वाइस चेयरमैन

प्रकाश टंडेल, वाइस चेयरमैन हरीश टंडेल, जनरल सेक्रेटरी कैलाश शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी अल्पेश उपाध्याय, कोषाध्यक्ष अंजो ज टंडेल, जॉइंट ट्रेजरर सुधीर पटेल, ईश्वर टंडेल, नीलेश टंडेल, हरेश टंडेल, उमेश मित्तल, दिनेश मित्तल और डीएमए की चेयरमैन वैशाली भट्ट, जॉइंट सेक्रेटरी प्राजक्ति टंडेल, ट्रेजरर

(पेज 8 का शेष समाचार)

इंडियन कोस्टगार्ड-असम राइफलस एजुकेशनल एक्सचेंज...

एसएआर में उनकी भूमिका के बारे में सीधे अनुभव मिला। ज्ञान साझा करने और स्वस्थ शैक्षणिक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कोस्टगार्ड पब्लिक स्कूल और असम राइफल पब्लिक स्कूल के छात्रों के बीच एक क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। भाईचारा और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए कोस्टगार्ड पब्लिक स्कूल और असम राइफल पब्लिक स्कूल के छात्रों के बीच बास्केटबॉल, फुटबॉल और रस्साकशी सहित दोस्ताना खेल कार्यक्रम आयोजित किए

गए। इंडियन कोस्टगार्ड एयर स्टेशन दमण की यात्रा के दौरान, छात्रों को एक कोस्टगार्ड फिल्म दिखाकर, आग बुझाने का प्रदर्शन और वॉटर केनन डिस्प्ले, विमान और उपकरणों का प्रदर्शन करके भूमिका, मिशन और परिचालन कार्यप्रणाली के बारे में व्यापक जानकारी दी गई। डीआईजी एसएसएन बाजपेयी, कमांडिंग ऑफिसर, कोस्टगार्ड दमण ने 18 दिसंबर 2025 को इंडियन कोस्टगार्ड एयर स्टेशन दमण की यात्रा के दौरान छात्रों से बातचीत की। कोस्टगार्ड एयर

बिजली मंत्रालय आयात होने वाले सामानों की सूची तैयार कर रहा.....लोकल उत्पादन पर जोर

Analysis of Import

Electronic Goods in India

नई दिल्ली ।

बिजली मंत्रालय वर्तमान में आयात होने वाले बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण वस्तुओं की सूची तैयार करने के लिए उद्योग के साथ काम में जुटा है। इसका मकसद इन वस्तुओं के लोकल उत्पादन के लिए मदद देना है। सूची में सब सी के बल्ब्स, परमानेंट मैनेनेट्स और उच्च चालकता वाली तांबे की छड़ें शामिल हैं। बिजली मंत्रालय की शाखा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने उद्योग निकाय इंडियन इलेक्ट्रिकल इंड्रिपमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) को भेज पत्र में कहा, 'मौजूदा परिदृश्य में यह पहल जरूरी है, क्योंकि बिजली क्षेत्र उन्नत उपकरणों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। आयात पर निर्भरता के कारण इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जोखिम

जुड़े हैं और इनकी कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता है।' इन वस्तुओं के लोकल उत्पादन से केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बल मिलेगा और इनके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ग्रिड का लचीलापन और ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सीईए ने कहा, मंत्रालय के लिए आर्थिक रूप से ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक यथार्थवादी, उद्योग-समर्थित मूल्यांकन आवश्यक है। प्राधिकरण ने आईईईएमए और एबीबी, आर्टिल्य बिड़ला, ह्योसंग, पॉलिकैब, डोंग-वू क्रांटम इंडिया, स्टरलाइट, रनाइडर, तोशिबा, केईसी और ज़िंदल एल्युमीनियम सहित उद्योग जागत के प्रमुख हितधारकों के साथ हाल ही में परामर्श के माध्यम से 73 महत्वपूर्ण वस्तुओं की एक सूची बनाई है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट में बड़ी बढ़त की तैयारी: नए ड्रोन, एयर डिफेंस और अटैक वेपन खरीदेगी सरकार

नई दिल्ली(ईएमएस)। भारत की सुरक्षा चुनौतियां दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं। खासकर पड़ोसी देशों से आने वाले खतरों को देखते हुए भारतीय सेना को और मजबूत बनाने की जरूरत है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम है। इस ऑपरेशन के बाद रक्षा मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए रक्षा बजट में करीब 20 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी मांगने की तैयारी कर रहा है। अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। यह हमला सिर्फ सीमा पर से नहीं, बल्कि भारत के अंदर धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश था। जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को सटीक हमलों से तबाह कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइलें, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें भेजीं, लेकिन भारत की मल्टी-लेयर एयर डिफेंस ने उन्हें रोक दिया। यह ऑपरेशन सिर्फ 4-5 दिनों का था, लेकिन इसने भारत की सैन्य ताकत और स्वदेशी हथियारों की विप्लवसीयता दुनिया के सामने दिखा दी। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत अब स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट की पुरानी नीति से आगे बढ़ चुका है। अब आतंकवाद के खिलाफ सीधा और तेज जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नया नॉर्मल कहा है- आतंकियों और उनके समर्थकों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। इसलिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी रक्षा बजट में बढ़ोतरी की वजह ऑपरेशन सिंदूर है। अब ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना जरूरी है। लंबी दूरी के हमलावर हथियार (स्टैंडऑफ वेपन्स) की कमी महसूस हुई। तेजी से आधुनिकीकरण (मॉडर्नाइजेशन) और सैन्य तैयारी बढ़ाने की आवश्यकता है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने हाल ही में कहा कि भारत का टफ नेबरहुड और लंबी अवधि की सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए बजट में बड़ी बढ़ोतरी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त मंत्रालय इसका समर्थन करेगा। **वर्तमान रक्षा बजट कितना** वित्तीय वर्ष 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले साल से करीब 9.5 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें डिफेंडल खर्च (नए हथियार और उपकरण खरीदने के लिए) 1.80 लाख करोड़ रुपये, रेवेन्यू खर्च (वेतन, रखरखाव, ईंधन आदि) करीब 3.12 लाख करोड़ रुपये, पेंशन खर्च 1.61 लाख करोड़ रुपये, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 26,817 करोड़ रुपये है। इस बजट का बड़ा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत अभियान पर खर्च होता है। 75 प्रतिशत कैपिटल खर्च स्वदेशी कंपनियों से खरीदारी के लिए रखा जाता है।

(पेज 8 का शेष समाचार)

दमण-दीव के 65वें मुक्ति दिवस पर भारतीय तटरक्षक...

प्रदर्शित किया गया। तटरक्षक डॉर्नियर विमान ने खोज और बचाव अभियानों में हवाई समन्वय का प्रदर्शन किया, जबकि एयर कुशन वाहन ने समुद्र तटीय सुरक्षा और बचाव अभियानों में अपनी बहुमुखी क्षमता दर्शाते हुए बीचिंग और उच्च गति वाली चालें प्रदर्शित

कीं। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में भारतीय तटरक्षक बल, जिला मुख्यालय संख्या 1 (दक्षिण गुजरात, दमण और दीव), पोरबंदर के कमांडर, उप महानिरीक्षक पंकज अग्रवाल उपस्थित थे। दीव के कलेक्टर राहुल देव बूरा सहित नागरिक

प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह में शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर दीव तट के समीप दो तटरक्षक पोतों को रोशन किया गया। ऑपरेशनल डेमो का आयोजन भारतीय तटरक्षक स्टेशन वेरावल द्वारा दीव प्रशासन के सहयोग से किया गया।

(पेज 8 का शेष समाचार)

दिलीपनगर डेवलपमेंट एसोसिएशन ने मनाया दमण-दीव...

वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर उपस्थित सभी ने वंदे मातरम् को गायकर उसको सम्मानित किया। डीडीए और डीएमए के सभी सदस्यों को दिलीपनगर डेवलपमेंट एसोसिएशन के 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली वर्ष मनाते हुए सभी को मोमेंटो प्रदान किया गया। इस मौके पर डीडीए चेयरमैन लखम टंडेल, वाइस चेयरमैन

प्रकाश टंडेल, वाइस चेयरमैन हरीश टंडेल, जनरल सेक्रेटरी कैलाश शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी अल्पेश उपाध्याय, कोषाध्यक्ष अंजो ज टंडेल, जॉइंट ट्रेजरर सुधीर पटेल, ईश्वर टंडेल, नीलेश टंडेल, हरेश टंडेल, उमेश मित्तल, दिनेश मित्तल और डीएमए की चेयरमैन वैशाली भट्ट, जॉइंट सेक्रेटरी प्राजक्ति टंडेल, ट्रेजरर

(पेज 8 का शेष समाचार)

इंडियन कोस्टगार्ड-असम राइफलस एजुकेशनल एक्सचेंज...

एसएआर में उनकी भूमिका के बारे में सीधे अनुभव मिला। ज्ञान साझा करने और स्वस्थ शैक्षणिक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कोस्टगार्ड पब्लिक स्कूल और असम राइफल पब्लिक स्कूल के छात्रों के बीच एक क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। भाईचारा और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए कोस्टगार्ड पब्लिक स्कूल और असम राइफल पब्लिक स्कूल के छात्रों के बीच बास्केटबॉल, फुटबॉल और रस्साकशी सहित दोस्ताना खेल कार्यक्रम आयोजित किए

गए। इंडियन कोस्टगार्ड एयर स्टेशन दमण की यात्रा के दौरान, छात्रों को एक कोस्टगार्ड फिल्म दिखाकर, आग बुझाने का प्रदर्शन और वॉटर केनन डिस्प्ले, विमान और उपकरणों का प्रदर्शन करके भूमिका, मिशन और परिचालन कार्यप्रणाली के बारे में व्यापक जानकारी दी गई। डीआईजी एसएसएन बाजपेयी, कमांडिंग ऑफिसर, कोस्टगार्ड दमण ने 18 दिसंबर 2025 को इंडियन कोस्टगार्ड एयर स्टेशन दमण की यात्रा के दौरान छात्रों से बातचीत की। कोस्टगार्ड एयर

स्टेशन दमण की यात्रा से छात्रों को समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी, मानवीय सहायता और खोज और बचाव कार्य की सीधी समझ हासिल हुई। दमण अपने सुंदर समुद्र तट, ऐतिहासिक विरासत और रणनीतिक समुद्री महत्व के साथ, छात्रों के लिए सीखने का एक आदर्श माहौल प्रदान करता है। इस यात्रा ने उन्हें शिक्षा को भारत की तटीय सुरक्षा, समुद्री विरासत और समुद्री पर्यावरण को संरक्षित करने के महत्व के साथ जोड़ने का अवसर दिया।

(पेज 8 का शेष समाचार)

ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए रखोली, कराड एवं सायली...

बताया। ग्राम पंचायत द्वारा यह आवश्यकता दिनांक 2025 में प्राप्त पंचायत सूचियों को तैयार करने से लेते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किया जाएगा तथा योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा।

चीनी उद्योग की चिंताओं को दूर करने अगले माह कुछ कदम उठाएगी केंद्र सरकार

केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने दिया भरोसा

नई दिल्ली ।

केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि केंद्र चीनी उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए अगले माह कुछ फैसले करेगी। दरअसल, मांग से अधिक उत्पादन होने के कारण गन्ने का बकाया बढ़ने लगा है। यह फैसला चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की लंबे समय से लंबित मांग से जुड़ा है। चीनी कारोबार चीनी का एमएसपी मौजूदा 22 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर करीब 41 रुपये प्रति किलोग्राम करने की मांग कर रहा है। इस क्रम में उद्योग गन्ने से एथनॉल बनाने के मौजूदा 28 प्रतिशत को बढ़ाकर आदर्श रूप से 50 प्रतिशत करने और चीनी का निर्यात मौजूदा 15 लाख टन से बढ़ाने की मांग भी कर रहा है। चीनी सत्र अक्टूबर से सितंबर तक होता है।

केंद्रीय खाद्य सचिव चोपड़ा ने इंडियन शुगर एंड बाईो-एनर्जी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (इस्मा) की वार्षिक बैठक में कहा, 'देखिए, वर्तमान में गन्ना बकाया ज्यादा बढ़ा नहीं है। हमें बताया गया है कि अगले महीने तक बकाया बढ़ना शुरू होगा। फिर खसत से अधिक चीनी का उत्पादन (2025-26 सत्र में) किसानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। यह हम नहीं चाहते हैं। इसलिए अधिशेष को कम करने के लिए हम जो कुछ और कर सकते हैं, और यकीनन करने वाले हैं। चोपड़ा ने कहा कि वर्तमान में उद्योग कदमों के साथ इस्मा ने अनुमान लगाया है कि 2025-26 सत्र के अंत तक चीनी का समापन स्टॉक करीब 60 लाख टन होगा और सरकार इस कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी ताकि किसानों को बढ़ते बकाया के कारण नुकसान न हो।

उधर इस्मा के निवर्तमान अध्यक्ष गौतम गौयल ने कहा कि उनके प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 30 नवंबर तक महाराष्ट्र में गन्ना बकाया पहले ही करीब 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है जबकि उत्तर प्रदेश के आंकड़े अभी भी प्रतीक्षित हैं। दरअसल, मॉनसून की अवांछ बढ़ने के कारण उत्तर प्रदेश में पेरार्डि देर से शुरू हुई। देश के कुल चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है।



भारत-अमेरिका संबंधों के नए स्वर, शांति, स्थिरता और रणनीतिक संतुलन की ओर



कातिलाल मांडोट

मोदी-ट्रंप वार्ता ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत-अमेरिका संबंध आज केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं। वे एक गहन, बहुआयामी और गतिशील साझेदारी के द्वार पर खड़े हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के समाधान से लेकर व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्रों में नवीन सहयोग हर स्तर पर यह रिश्ता नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि आने वाले वर्षों में दोनों देश एक-दूसरे के लिए अपरिहार्य रणनीतिक सहयोगी बनेंगे।

भारत और अमेरिका के बीच हाल के दिनों में हुई उच्च स्तरीय वार्ता ने वैश्विक राजनीति में एक नया संदेश दिया है।संवाद हो वह सेतु है जो किसी भी जटिल द्विपक्षीय रिश्ते को संतुलन और स्थिरता की ओर ले जाता है। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य, वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव और सामरिक चुनौतियों के बीच दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत न केवल समयोचित थी बल्कि भविष्य की साझेदारी के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण भी प्रकट करती है। लंबे समय से चले आ रहे विवाद, खासकर व्यापार और टैरिफ से जुड़े मुद्दे, धीरे-धीरे नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। भारत के लिए यह बातचीत एक भरोसेमंद संकेत है कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से दो देश फिर से सामरिक और आर्थिक तालमेल की ओर लौट रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बताया कि यह वार्ता महत्वपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हो। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों ने विवादित मुद्दों से आगे बढ़कर उन क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं।जैसे रक्षा, ऊर्जा, सैन्य नवाचार, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और सुरक्षा। वीते कुछ वर्षों में व्यापारिक टकराव, विशेषकर टैरिफ की नीति, भारत-अमेरिका संबंधों में एक बड़ी बाधा थी। अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्कों को लेकर कई बार तनाव की स्थिति बनी। किंतु वास्तविकता यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी विविध, लचीली और मजबूत हो चुकी है कि इन टैरिफ का प्रभाव सीमित रहा। दूसरी ओर, अमेरिका को यह समझ आ गया कि कठोर व्यापारिक नियमों से वह भारत जैसे तेजी से उभरते साझेदार को केवल असहज कर रहा है, लाभ नहीं। इसलिए, जैसे-जैसे वार्ता आगे बढ़ी, टैरिफ का भूत धीरे-धीरे समाप्त होता दिखा।

इस संवाद का सबसे बड़ा संदेश यह है कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत और अमेरिका केवल सहयोग करने की इच्छा नहीं बल्कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता रखते हैं। दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में उभर रही साझा चुनौतियाँ,चाहे वह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा हो, उभरती तकनीकों का भविष्य हो, या ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु संबंधी मुद्दे।इन सब पर संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं। यह समझ इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक विमर्श को आकार देने वाला निर्णायक खिलाड़ी है।



वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलु यह था कि दोनों देशों ने अपने रणनीतिक हितों के प्रति स्पष्टता बरतते हुए व्यापारिक रिश्तों को नई ऊर्जा देने की आवश्यकता को स्वीकार किया। भारत में मौजूद अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि पहले ही अंतिम प्रस्ताव वॉशिंगटन भेज चुके हैं और अब समझौते का निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिया जाना है। यह संकेत देता है कि आने वाले महीनों में दोनों देश एक बड़े व्यापारिक समझौते के करीब पहुँच सकते हैं। मुद्दों को टालने या कठोर रुख अपनाने की बजाय संवाद द्वारा रास्ता खोजने का यह सकारात्मक संकेत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी आवश्यककारी है।

अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया 9 करोड़ का गोल्ड कार्ड भी दोनों देशों के रिश्तों में एक नया आयाम जोड़ता है। यह स्थायी निवास और निवेश के अवसरों को जोड़ने का प्रयास है, लेकिन इसकी अत्यधिक लापरवाही इसे आम लोगों के लिए कठिन बनाती है। इसके अलावा, यह भी तथ्य है कि अमेरिका कभी भी किसी कार्डधारक का स्टेटस बदल सकता है, जिससे यह नीति अस्थिरता का संकेत भी देती है। भारत के लिए चुनौती यह है कि हजारों एच-1बी वीजा आवेदकों के इंटरव्यू अचानक महीनों के लिए टाल दिए गए हैं। इससे अमेरिकी नीतियों की अनिश्चितता उजागर होती है। अमेरिका के भीतर भी इस गोल्ड कार्ड योजना का विरोध जारी है, क्योंकि इसे अमेरिका के हितों के विरुद्ध और कुछ

देशों को अनावश्यक रूप से अलग-थलग करने वाला कदम माना जा रहा है। यह भी तथ्य है कि कई विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका अपने कठोर और बदलते नियमों के माध्यम से भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक तरक्की पर किसी न किसी रूप में अंकुश लगाने की कोशिश करता है। लेकिन यह आकलन भी उतना ही सही है कि भारत अब ऐसी नीतियों के दबाव में नहीं आने वाला। भारत की वैश्विक स्थिति जितनी मजबूत हुई है, उतनी ही उसकी क्षमता बढ़ी है कि वह समानता और सम्मान के आधार पर साझेदारी को आगे बढ़ाए। यही कारण है कि इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टैरिफ का मुद्दा उठाने की आवश्यकता तक महसूस नहीं की।क्योंकि भारत का आत्मविश्वास अब किसी रक्षात्मक मुद्रा का मोहताज नहीं रहा।

इस पूरे संवाद का व्यापक संदर्भ यह है कि दुनिया अनेक मोर्चों पर तनाव की स्थिति से गुजर रही है।यूरोप और मध्यपूर्व में संघर्ष, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन, और आर्थिक अनिश्चितताएँ। ऐसी परिस्थितियों में भारत-अमेरिका संबंधों की स्थिरता न केवल दोनों देशों बल्कि पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। एक तरफ अमेरिका अपनी वैश्विक भूमिका को पुनर्संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर भारत एक उभरती शक्ति के रूप में वैश्विक नेतृत्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित कर चुका है। इस

संतुलन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संवाद और सहयोग ही सबसे प्रभावी साधन हैं। इस बातचीत से यह भी प्रतीत होता है कि दोनों देश भविष्य में सैन्य और सुरक्षा साझेदारी को और सुदृढ़ करेंगे। 21वीं सदी की रक्षा तकनीक चाहे वह साइबर सुरक्षा हो, स्पेस सिस्क्रॉप्टी, एआई आधारित सैन्य प्रणालियाँ, या समुद्री सुरक्षा,इन सभी क्षेत्रों में भारत और अमेरिका मिलकर वैश्विक मानक तय करने में सक्षम हैं। यह सहयोग न केवल एक-दूसरे के हितों की रक्षा करेगा बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति में भी योगदान देगा।

अमेरिका द्वारा भारत को दबावे की कोशिश का दौर अब बीतता दिख रहा है। दुनिया जानती है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला देश नहीं है। यही कारण है कि इस वार्ता के परिणाम में अमेरिका खुद एक अधिक सम्मानजनक, विनम्र और वास्तविक साझेदार के रूप में सामने आया। भारत के साथ संबंधों को गहराने की अमेरिका की इच्छा केवल रणनीतिक आवश्यकता नहीं बल्कि व्यावहारिक अनिवार्यता बन चुकी है।

इन सबके बीच यह भी ध्यान देने योग्य है कि वैश्विक स्तर पर अन्य देश जैसे मैक्सिको भी नई परिस्थितियों में अपने आर्थिक हितों के लिए कठोर टैरिफ नीतियाँ अपनाने की बात कर रहे हैं। यह विश्व अर्थव्यवस्था में उभरती नई प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। ऐसे समय में भारत को न केवल अमेरिका बल्कि अन्य साझेदारों के साथ भी अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सजग रहना होगा। आने वाले समय में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका निर्णायक होगी।

अंततः मोदी-ट्रंप वार्ता ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत-अमेरिका संबंध आज केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं। वे एक गहन, बहुआयामी और गतिशील साझेदारी के द्वार पर खड़े हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के समाधान से लेकर व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्रों में नवीन सहयोग हर स्तर पर यह रिश्ता नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि आने वाले वर्षों में दोनों देश एक-दूसरे के लिए अपरिहार्य रणनीतिक सहयोगी बनेंगे। भारत की बढ़ती शक्ति, आत्मविश्वास और वैश्विक नेतृत्व क्षमता ने उसे वह स्थान दिलाया है जहाँ कोई भी राष्ट्र उसे दबा नहीं सकता।संवाद ही एकमात्र रास्ता है। यही इस वार्ता का सार है और यही भविष्य के भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा तय करेगा।

संपादकीय

मनरेगा अब ‘जी राम जी’

शुक्रवार, 19 दिसंबर, संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। सरकार का प्रयास रहेगा कि मनरेगा का वैकल्पिक बिल हृदयकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)ह्द दोनों सदनों में पारित हो जाए, ताकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे कानून के तौर पर अधिसूचित किया जा सके। नए बिल को संक्षेप में हज़ी-राम-जीह्द कहा जा रहा है। शायद इसीलिए हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों की खिचड़ी बनाई गई है। इसे भाजपा की ह्दामनवादी राजनीतिह्द से जोड़ कर भी देखा जा रहा है। यह मानसिकता का संकरापन है। बुनियादी चिंता और सरोकार यह होना चाहिए कि जिस भारतीयों को काम का संवैधानिक अधिकार हासिल है, क्या उसे 100 अथवा 125 दिन का रोजगार मुहैया कराया जा रहा है अथवा नहीं? जब 2005 में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के दौरान ह्दाराष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बिलह्द तैयार किया गया था, तब भाजपा के वरिष्ठ सांसद कल्याण सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति में बिल पर व्यापक विमर्श किया गया था। संसदीय समिति ने तत्कालीन मनमोहन सरकार को कई सुझाव भी दिए थे। हमारी सूचना है कि अधिकांश सुझाव मान लिए गए थे। यकीनन वह एक ऐतिहासिक प्रयोग था कि देश में गरीब और बेरोजगार अथवा जिसे काम चाहिए, उस व्यक्ति को साल में कमोबेश 100 दिन का रोजगार, केंद्र सरकार के जरिए, उपलब्ध कराया जाएगा। वह सफल्य और कानूनी प्रावधान अछूरे ही रहे, क्योंकि 2006-07 से लेकर 2024-25 तक औसतन 50.24 दिन का रोजगार ही मुहैया कराया जा सका है। वाकई यह सरकार की नाकामियों का स्मारक भी है, लेकिन इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही सरकारें शामिल रही हैं। साल 2008 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की राफत सामने आई, तो बर्दश्तजामी और गहरे भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। करीब 70 फीसदी ब्लॉक में मनरेगा अफसर ही तैनात नहीं थे। करीब 52 फीसदी पंचायतों में मनरेगा सहायक ही नहीं थे। बंगाल के 19 जिलों में बिना काम ही भुगतान किए गए और फंड के गलत इस्तेमाल किए गए। देश के 19 राज्यों में सर्वे कराए गए, तो अधिकारी और ठेकेदार के मिलीभगत भ्रष्टाचारों का खुलासा हुआ। 2024-25 में, मोदी सरकार के दौरान, 193 करोड़ रूपए का गबन और घोटाला पाया गया। 2025-26 में 23 राज्यों में मनरेगा के तहत या तो काम ही नहीं कराया गया अथवा बजटीय खर्च कम किया गया। बीती 5 दिसंबर को ही राज्यसभा में सरकार ने जानकारी दी थी कि मनरेगा की मद के 9746 करोड़ रूपए बकाया हैं। बजट में मनरेगा के लिए 80,000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे। चूंकि रकम खर्च नहीं की गई, लिहाजा साफ है कि मजदूरी बांटी नहीं गई, क्योंकि काम उपलब्ध ही नहीं कराया गया। यूपीए सरकार के दौरान ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कुछ पेशेवरों, पत्रकार आदि, को प्रतिनिधि बना कर बुदेलखंड जैसे पिछड़े इलाकों में भेजा था, ताकि मनरेगा का यथार्थ सामने आ सके।

चिंतन-मनन

ईमानदारी सर्वोत्तम

एक राजा ने अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए राज्य के सभी नौजवानों को एक-एक बीज दिया और कहा, इसे गमले में लगाकर सींचना और एक वर्ष के पश्चात मेरे पास लेकर आना। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा, उसे राजा घोषित किया जाएगा। सब बीज लेकर खुशी-खुशी लौटे। पाँच-छह दिन गुजर जाने पर भी जब बीज अंकुरित नहीं हुआ, तो सबने उसी प्रकार का बीज नर्सरी से खरीदकर अपने-अपने गमले में लगा दिया और सींचने लगे। इन सबमें केवल भोलू नाम का नौजवान ही 7सा था, जिसने दूसरा बीज खरीदने का दुस्साहस नहीं किया। कुछ दिनों के पश्चात सभी युवा अपने-अपने हरे-भरे गमले के साथ राजा के सम्मुख पेश हुए, केवल भोलू ही खाली गमले के साथ कोने में नजरें चुराए खड़ा था। राजा ने उसे पास बुलाया और घोषणा कर दी कि भोलू ही मेरा उत्तराधिकारी है। जब जनता ने उसके खाली गमले को प्रश्नवाचक नजरों से देखा, तो राजा ने सभी के समक्ष यह भेद खोला कि मैंने उबले हुए बीज सभी को दिए थे। भोलू ने उसी उबले बीज को सींचा, जबकि शेष सभी ने राजा बनने के लिए बीज बदल लिए। ये बड़े-बड़े पौधे बेईमानी की कहानी कह रहे हैं। सत्य तो यही है कि बीज तो अंकुरित होना ही नहीं था, बावजूद इसके भोलू हिम्मत व ईमानदारी से अपना खाली गमला ही मेरे पास लेकर आया। इसलिए अगला राजा भोलू ही होगा। यदि हम बुद्धि रूपी जमीन पर ईमानदारी का बीजारोपण कर उसे सींचेंगे, तो निसर्देह उस पर विश्वास रूपी मीठे फल निकलेगें।



सौरभ जैन अखित

बालादेश एक बार फिर गंभीर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। भारत विरोधी बयानबाजी के लिए चर्चा में रहे श्रीरफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका समेत कई शहरों में भड़की हिंसा ने नई चिंगाएँ खड़ी कर दी हैं। अखबारों के दफ्तर जलाए गए, अवामी लोग के कार्यालय पर हमले हुए और भारतीय उच्चायोग को घेरने की घटनाएँ सामने आईं। विगड़ते हालात के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश भी धीरे-धीरे पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी संगठनों के हाथ



ललित गर्ग

अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2005 में घोषित किया था और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सत विकास और विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूक करना है, ताकि वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटा जा सके। इस दिवस को मनाते हुए मुख्य विचार है कि ह्दएकजुटता में नवाचार और प्रौद्योगिकीह्द, ह्दयुवा-नेतृत्व वाली एकजुटताह्द और ह्दसतत विकास लक्ष्यों के लिए एकजुटताह्द जैसे विषयों पर केन्द्रित है। आज की दुनिया एक विचित्र और विरोधाभासी दौर से गुजर रही है। एक ओर विज्ञान, तकनीक और संचार ने पूरी पृथ्वी को एक छोटे से गाँव में बदल दिया है, तो दूसरी ओर मनुष्यों के बीच की दूरी, गरीबी, अशिक्षा, अविश्वास और वैमनस्य लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध, आतंक, हिंसा, नस्लवाद, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक असमानता ने मानव सभ्यता के मूल उद्देश्य पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता एवं एकजुटता दिवस न केवल नये मानवीय मूल्यों से प्रेरित समतामूलक समाज-संरचना की प्रेरणा है, बल्कि मानव जाति के लिए आत्मसंयन और आत्मसुधार का अवसर है। इस दिवस की मूल भावना यही है कि गरीबी का उन्मूलन हो, विकास अंतिम आदमी तक पहुँचे, मनुष्य पहले मनुष्य बने, उसके बाद उसकी पहचान राष्ट्र, धर्म, भाषा, रंग या विचारधारा से हो। आज जब दुनिया अनेक खेमों में बँटती जा रही है, तब ह्दसभी मानव पहले मानवह्द की चेतना को पुनः जाग्रत करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। भारतीय चिंतन ने सदियों पहले ह्दसयुधैव कुटुम्बकम्ह्द का जो सूत्र दिया था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया

का खिलौना बनने जा रहा है? भारत की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि बांग्लादेश में सक्रिय कुछ कट्टरपंथी इस्लामी संगठन दोबारा सिर उठा रहे हैं। जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और हिज्ब-उत-तहरीर जैसे संगठनों का अतीत हिंसा, बम धमाकों और दारोगे किलिंग से जुड़ा रहा है। शेख हसीना सरकार के समय इन पर सख्त कार्रवाई हुई थी, जिससे इनका नेटवर्क कमजोर पड़ा। लेकिन मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक ढील के माहौल में इनके फिर से सक्रिय होने की आशंका बढ़ गई है। भारत के लिए चिंता की एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का संपर्क बांग्लादेशी कट्टरपंथी गुटों से रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये संगठन भारत के पूर्वी हिस्से में अस्थिरता फैलाने के इरादे से बांग्लादेश को एक नए आधार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ आकलनों में यह भी सामने आया है कि विश्वविद्यालयों और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में बांग्लादेशी गुट इन आतंकी संगठनों

की मदद कर रहे हैं। भारत-बांग्लादेश के बीच लंबी और संवेदनशील सीमा भी इस खतरे को बढ़ाती है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय से लगी सीमा पहले से ही अनेध चुसपैठ, तस्करी और नकली नोटों की समस्या से जूझ रही है। यदि कट्टरपंथी संगठनों को यहाँ पनपने का मौका मिला, तो यह सीमा आतंकियों के लिए आगमागह के साथ ही एक देश से दूसरे देश तक आवाजाही, स्लीपर सेल और हथियारों की तस्करी का रास्ता बन सकती है, जैसा पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर देखा गया है। हालिया हिंसा में भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा भी चिंता का संकेत है। चर्चायां में भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी और भारत विरोधी नारों से यह साफ होता है कि कट्टरपंथी तत्व माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति और सामाजिक दिशा का सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से



मजबूत रहे हैं। ऐसे में कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त नीति, मजबूत और स्थिर सरकार तथा दोनों देशों के बीच खुफिया और सुरक्षा सहयोग बेहद जरूरी है। यदि समय रहते हालात पर काबू नहीं पाया गया, तो आशंका है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह आतंकी नेटवर्क के लिए उपजाऊ जमीन बन सकता है, जो भारत के लिए दीर्घकालिक और गंभीर चुनौती साबित होगा।

मानव एकजुटता से ही बचेगा मानव-सभ्यता का अस्तित्व

है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, बल्कि यह भी है कि परिवार के हर सदस्य सहायता करना नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में संवेदनशीलता, करुणा, समानता और सहानुभूति को अपनाना है। जब हम किसी दूसरे देश के युद्ध पीड़ितों को केवल समाचार की सुर्खी मानकर आंग बढ़ जाते हैं, तब हमारी मानवता कहीं न कहीं मर जाती है। जब शरणार्थियों को बोझ समझा जाता है और गरीब देशों की पीड़ा को अनदेखा किया जाता है, तब वैश्विक एकता का विचार खोखला प्रतीत होता है। मानव एकता का संदेश यह है कि किसी भी कोने में बहाया गया रक्त, पूरी मानवता को अहत करता है और कहीं भी बहाया गया आँसू, हमारी सामूहिक अस्फुलता का प्रतीक है। वह दिवस हमें सिखाता है कि विविधता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भाषाएँ अलग हों, पूजा-पद्धतियाँ अलग हों, पर मनुष्य की पीड़ा, उसकी आशा और उसका सपना हर जगह एक जैसा होता है। हिंसा और युद्ध के इस दौर में शांति की भाषा बोलना साहस का कार्य है। शांति केवल हथियारों के मौन का नाम नहीं, बल्कि न्याय, समानता और सम्मान से उपजा हुआ विश्वास है। जब तक दुनिया में गहरी आर्थिक असमानता रहेगी, जब तक कुछ देशों का विकास दूसरों के शोषण पर आधारित रहेगा, तब तक वास्तविक मानव एकता संभव नहीं है। इसलिए मानव एकजुटता दिवस सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी माँग करता है। यह याद दिलाता है कि संपन्नता का उद्देश्य केवल उपभोग नहीं, बल्कि साझेदारी है और शक्ति का उद्देश्य केवल प्रभुत्व नहीं, बल्कि संरक्षण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा, मीडिया और राजनीति मानव एकता के मूल्यों को बढ़ावा दें। बच्चों को प्रारंभ से ही यह सिखाया जाए कि दूसरे का दर्द समझना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं में वैश्विक नागरिकता के संस्कृति और साझा करने की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की घोषणा जैसी पहलों के माध्यम से, एकजुटता की अवधारणा को गरीबी के खिलाफ लड़ाई में और सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी

में महत्वपूर्ण के रूप में बढ़ावा दिया गया। मानव एकजुटता का अर्थ केवल संकेत के समय सहायता करना नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में संवेदनशीलता, करुणा, समानता और सहानुभूति को अपनाना है। जब हम किसी दूसरे देश के युद्ध पीड़ितों को केवल समाचार की सुर्खी मानकर आंग बढ़ जाते हैं, तब हमारी मानवता कहीं न कहीं मर जाती है। जब शरणार्थियों को बोझ समझा जाता है और गरीब देशों की पीड़ा को अनदेखा किया जाता है, तब वैश्विक एकता का विचार खोखला प्रतीत होता है। मानव एकता का संदेश यह है कि किसी भी कोने में बहाया गया रक्त, पूरी मानवता को अहत करता है और कहीं भी बहाया गया आँसू, हमारी सामूहिक अस्फुलता का प्रतीक है। वह दिवस हमें सिखाता है कि विविधता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भाषाएँ अलग हों, पूजा-पद्धतियाँ अलग हों, पर मनुष्य की पीड़ा, उसकी आशा और उसका सपना हर जगह एक जैसा होता है। हिंसा और युद्ध के इस दौर में शांति की भाषा बोलना साहस का कार्य है। शांति केवल हथियारों के मौन का नाम नहीं, बल्कि न्याय, समानता और सम्मान से उपजा हुआ विश्वास है। जब तक दुनिया में गहरी आर्थिक असमानता रहेगी, जब तक कुछ देशों का विकास दूसरों के शोषण पर आधारित रहेगा, तब तक वास्तविक मानव एकता संभव नहीं है। इसलिए मानव एकजुटता दिवस सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी माँग करता है। यह याद दिलाता है कि संपन्नता का उद्देश्य केवल उपभोग नहीं, बल्कि साझेदारी है और शक्ति का उद्देश्य केवल प्रभुत्व नहीं, बल्कि संरक्षण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा, मीडिया और राजनीति मानव एकता के मूल्यों को बढ़ावा दें। बच्चों को प्रारंभ से ही यह सिखाया जाए कि दूसरे का दर्द समझना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं में वैश्विक नागरिकता के संस्कृति और साझा करने की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की घोषणा जैसी पहलों के माध्यम से, एकजुटता की अवधारणा को गरीबी के खिलाफ लड़ाई में और सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी



मानवाधिकार और सामाजिक विकास संबंधी पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य एक ऐसी समतापूर्ण दुनिया का निर्माण करना है जहाँ सभी को विकास के अवसर प्राप्त हों। यह प्रतिबद्धता एकजुटता के आधारशिला के रूप में सार्वभौमिक प्राप्ति में गहरी आस्था को दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र की एकजुटता की अवधारणा ही उसके मिशन का आधार है। सामूहिक सुरक्षा एक ऐसा सिद्धांत है जो राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर इस बात पर जोर देता है कि सदस्य देशों को सहयोग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे राष्ट्र सशस्त्र संघर्ष या आतंकवाद जैसे किसी भी खतरे के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। वैश्विक चुनौतियों के परस्पर संबंध को पहचानते हुए, संयुक्त राष्ट्र गरीबी, भूख और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वकालत करता है। एकजुटता साझेदारी के माध्यम से प्रकट होती है जो संसाधनों के बंटवारे को बढ़ावा देती है और प्रत्येक राष्ट्र के प्रयासों को मजबूत करती है। अंततः मानव एकता एवं एकजुटता दिवस हमें एक सरल लेकिन गहन सत्य की ओर लौटने का आह्वान करता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका मनुष्य होना है। यदि हम इस पहचान को बचा पाए, तो युद्ध, आतंक और हिंसा की अंधेरी रात अपने आप छूटने लगेगी। वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को व्यवहार में उतारकर ही हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहाँ अस्तित्व भय से नहीं, विश्वास से संचालित हो; जहाँ शक्ति हथियारों में नहीं, करुणा में निहित हो; और जहाँ भविष्य की पीढ़ियाँ हमें एक ऐसी मानवता के रूप में याद करें, जिसने विभाजन नहीं, बल्कि एकता को चुना।

संक्षिप्त समाचार

‘रुस अगले साल भी युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहा’, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों से लगाई मदद

कीव, एजेंसी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रुस अगले साल भी युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहे हैं। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका से मदद देने की अपील की। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा, ‘आज हमें फिर से ऐसे संकेत मिले हैं कि मॉस्को अगले साल भी लड़ाई जारी रखने की तैयारी कर रहा है। ये संकेत सिर्फ हमारे लिए नहीं हैं बल्कि ये हमारे सहयोगी देशों के लिए भी संकेत हैं कि वे भी इसे देखें और न सिर्फ देखें बल्कि इस पर प्रतिक्रिया भी दें। खासकर अमेरिका, जो अवसर कहता है कि रुस इस युद्ध को खत्म करना चाहता है।’ जेलेंस्की ने आगे लिखा, ‘अमेरिका दावा करता है कि रुस, युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, वे बिल्कुल उलट हैं। रुस की मानसिकता को समझकर उसके हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। रुस कूटनीति को अहमियत नहीं देता और वह बस यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों को तबाह करना चाहता है। वह यूक्रेन की जमीन को चुराकर उसे कानूनी वैधता देना चाहता है। यूक्रेन के बाद रुस यूरोप का रुख करेगा, जहां वह यूरोप की जमीन को भी ऐतिहासिक रूप से रुस की जमीन बताएगा।’ जेलेंस्की ने इसके बाद लिखा कि यूक्रेन अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद की जरूरत है। साथ ही रुस की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई और राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी जरूरत है।

इसाइल ने गाजा के रिहायशी इलाके में दागे मोर्टार, 10 लोग घायल

येरूशलम, एजेंसी। इसाइल की सेना ने बुधवार को गाजा पट्टी के एक फलस्तीनी रिहायशी इलाके में मोर्टार गोला दागा। इस घटना में कम से कम 10 लोगों के घायल होने की पुष्टि स्वास्थ्य अधिकारियों ने की है। इसाइली सेना ने कहा कि यह फायरिंग संघर्षविराम समझौते में तय की गई तथाकथित ‘येलो लाइन’ के पास एक सैन्य अभियान के दौरान हुई। सेना के मुताबिक मोर्टार अपने तय लक्ष्य से भटक गया, हालांकि यह नहीं बताया गया कि लक्ष्य क्या था। सेना ने घटना की जांच शुरू कर दी है। गाजा सिटी के अल-अहली अस्पताल के निदेशक फादेल नईम ने बताया कि घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर से लागू संघर्षविराम के बाद यह पहली घटना नहीं है, जब येलो लाइन के बाहर इसाइली फायरिंग से नागरिक हताहत हुए हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संघर्षविराम के बाद अब तक इसाइली कार्रवाई में 370 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसाइल का कहना है कि उसने हमاس की उल्लंघनों के जवाब में कार्रवाई की है, जबकि फलस्तीनी पक्ष का आरोप है कि लाइन के स्पष्ट रूप से चिह्नित न होने के कारण आम नागरिक निशाना बन रहे हैं।

रैपर के फ्लॉक को गोलीबारी मामलों में 30 साल की सजा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी रैपर के फ्लॉक (केविन पेरेज) को ब्रॉन्क्स में 2020-21 के बीच हुई कई गोलीबारी घटनाओं में दोषी पाए जाने पर 30 साल की सजा सुनाई गई है। 22 वर्षीय रैपर पर चार अलग-अलग घटनाओं में कई लोगों को घायल करने और एक गैंग का मुखिया बनने का आरोप था। जज लुइस लिमन ने कहा कि पेरेज ने सोशल मीडिया पर हिंसा को बढ़ावा दिया और युवा प्रशंसकों को गलत संदेश दिया। मार्च में उन्हें रैकेटियरिंग साजिश और हत्या के प्रयास सहित कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

कोलंबिया में विद्रोहियों के हमले में दो पुलिस अफसरों की मौत

बोगोटा , एजेंसी। कोलंबिया के काली में नेशनल लिबरेशन आर्मी (ईएलएन) विद्रोहियों के हमले में दो पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। दोनों अधिकारी बाइक पर गश्त कर रहे थे, तभी सड़क किनारे लगाए बम से निशाना बनाया गया। घटना से पहले ईएलएन ने कैरेबियन में अमेरिकी सैन्य तैनाती के विरोध में 72 घंटे का आर्मुड स्ट्राइक शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक, सप्ताहांत में पुलिस स्टेशन व सैन्य ठिकानों पर भी हमले हुए, जिनमें एक एंबुलेंस चालक की मौत हुई।

बक रॉजर्स स्टार गिल जेराई का 82 साल की उम्र में कैंसर से निधन

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी अभिनेता गिल जेराई का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1979 की साइ-फाई सीरीज बक रॉजर्स इन 25 सेचुरी में मुख्य भूमिका निभाई थी। जेराई की पत्नी जेनेट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि जेराई को कैंसर था। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उनके साथ बिताया गया समय मेरे लिए कभी पर्याप्त नहीं हो सकता।

अमेरिकी सीनेटर ने भारत-चीन से आने वाली जेनेरिक दवाओं पर बढ़ती निर्भरता पर जताई चिंता

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका के एक बार फिर सक्रिय हुई है। सीनेटर स्कॉट इस मुद्दे पर समिति की वरिष्ठ सदस्य सीनेटर किस्टून गिलिब्रैंड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके तहत कई जांच, सुनवाई और सरकारी एजेंसियों और परिवार के साथ संवाद किए गए हैं। सीनेटर स्कॉट के अनुसार, अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं में लगभग 80 प्रतिशत एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) विदेशों से आते हैं। इनमें से कई दवाएं असुरक्षित और गंदी फैक्ट्रियों में तैयार हिस्सा विदेशों में बनता है। यह स्थिति न सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। रिक स्कॉट ने कहा, ‘जो भी अमेरिकी दूसरे देशों में बनी जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है, उसे अपनी दवाओं में छिपे इंग्रीडिएंट्स के बारे में जानने का हक है।’ स्कॉट की समिति अमेरिका की दवा आपूर्ति शृंखला में मौजूद

भारत-अमेरिका के व्यापार संबंधों के लिए 2026 की पहली तिमाही होगी काफी अहम: रिचर्ड रोसो

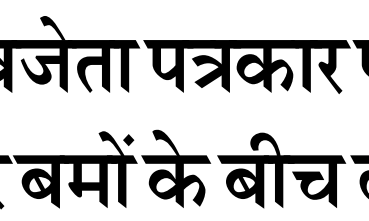
वाशिंगटन , एजेंसी। भारत और अमेरिका के रिश्तों ने साल 2025 में कई उतार-चढ़ाव देखे। साल की शुरुआत में जहां दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर अच्छी तेजी दिखी, वहीं आगे चलकर व्यापार से जुड़े मतभेद और कुछ भू-राजनीतिक मुद्दों पर असहमति भी सामने आईं। हालांकि अब हालात धीरे-धीरे स्थिर हो रहे हैं और दोनों देश 2026 को ज्यादा सकारात्मक और उत्पादक बनाने की दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यह बात अमेरिका में भारत मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ रिचर्ड रोसो ने एक साक्षात्कार में कही है। वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटैजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) में भारत और उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर काम कर रहे रिचर्ड रोसो ने समाचार एजेंसी आईएनएस से बातचीत में कहा, ‘यह रिश्ता साफ तौर पर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत उस देशों में शामिल था, जिन्होंने अमेरिका के साथ शुरुआत में ही बेहतर तरीके से संपर्क बनाया। इसमें राष्ट्राध्यक्ष को भी मुलाकात और क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जैसे अहम कदम शामिल थे। हालांकि, कुछ समय बाद मतभेद सामने आने लगे। रोसो ने बताया कि भारत-पाकिस्तान तनाव को लेकर अलग-अलग नजरिया है और भारत द्वारा रुस से तेल की खरीद जारी रखने पर



वांशिंगटन में चिंता बढ़ी। इसके बावजूद रोसो का मानना है कि मौजूदा दौर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा शांत है। उन्होंने कहा, ‘अब तक व्यापार समझौता पूरा नहीं हुआ है। रोज-रोज की तीखी बयानबाजी भी नहीं दिखती। यह माहौल 2026 में रिश्तों को ज्यादा मजबूत बनाने की नींव रख सकता है। व्यापार के मुद्दे पर रोसो ने माना कि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण बाजार रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिनसे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में निर्यात करना मुश्किल हुआ। ये नीतियां आज भी अमेरिका की सोच को प्रभावित करती हैं, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए से। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की व्यापार नीति में समय के साथ बदलाव आया है। आयात शुल्क में कटौती,

चीन के सपने को अमेरिका का झटका, ताइवान को 10 अरब डॉलर के हथियार देने को मंजूरी

बीजिंग, एजेंसी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चीन को कराा झटका दिया है। सालों से दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर की स्थिति है और अब रणनीतिक मोर्चे पर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है कि चीन को मिची लग सकती है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उस ताइवान को 10 अरब डॉलर के हथियार बेचने को मंजूरी दी है, जिससे चीन का तनाव बना रहता है। चीन का ताइवान पर दावा रहा है, जबकि ताइवानी नेतृत्व का जोर स्वतंत्र देश पर है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन अकसर आमने-सामने आते रहे हैं। यही नहीं 2022 में अमेरिकी नेता नैन्सी पेलेोसी भी ताइवान गई थीं और उस दौरान चीनी फाइटर जेट्स ने उनके विमानों का पीछ करने की कोशिश की थी। इससे काफी तनाव पैदा हो गया था। अमेरिका की ओर से मंजूरी किए गए पैकेज के तहत ताइवान को मध्यम दूरी की मिसाइलें दी जाएंगी। इसके अलावा होवित्जर तोपों और ड्रोनस की भी बिक्री शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार देर रात इन हथियार सौदों की घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित संबोधन के दौरान



लॉस एंजिलिस, एजेंसी। वियतनाम के धान के खेतों से लेकर इराक के रेगिस्तानों तक युद्धों की प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग दुनिया तक पहुंचाने वाले, गोलियों और बमों से बचते हुए दशकों तक काम करने वाले पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार पीटर अर्नेट का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एसोसिएटेड प्रेस के लिए वियतनाम युद्ध की रिपोर्टिंग पर 1966 में अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग का पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले अर्नेट का बुधवार को न्यूयॉर्क बीच में निधन हुआ। उनके बेटे एंड्रयू अर्नेट ने बताया कि उस समय वे दोस्तों और परिवार से घिरे हुए थे। उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके बेटे एंड्रयू अर्नेट ने



बताया कि वह प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। वायर सेवा संवाददाता के रूप में अर्नेट 1962 से 1975 में युद्ध समाप्त होने तक वियतनाम में रिपोर्टिंग करते रहे और उस दौरान वे मुख्य रूप से अन्य पत्रकारों के बीच ही जाने जाते थे। हालांकि 1991 में सीएनएन के लिए पहले खाड़ी युद्ध की लाइव रिपोर्टिंग करने के बाद वे आम लोगों के बीच भी

एक जाना-पहचाना नाम बन गए। एडिथ लेडजर 1972-73 में वियतनाम युद्ध के दौरान उनकी साथी व एसोसिएटेड प्रेस की संवाददाता थीं। उन्होंने कहा, पीटर अर्नेट अपने समय के युद्ध कवर करने वाले महान संवाददाताओं में से एक थे। वह निडर, साहसी और बेहतरीन लेखक थे। उनकी रिपोर्टिंग आने वाली पीढ़ियों के पत्रकारों और इतिहासकारों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। 1962 से 1975 तक अर्नेट वियतनाम में रिपोर्टिंग करते रहे। उन्होंने 1991 में पहले खाड़ी युद्ध के दौरान इराक से लाइव अपडेट देकर दुनियाभर में प्रसिद्धि हासिल की। अमेरिकी नेतृत्व वाले हमले से पहले अधिकांश पश्चिमी

विदेश

भारत-अमेरिका के व्यापार संबंधों के लिए 2026 की पहली तिमाही होगी काफी अहम: रिचर्ड रोसो

स्थानीय निर्माण की अनिवार्यता में कमी और ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ बड़े व्यापार समझौते इसके उदाहरण हैं। राजनीतिक स्तर पर आई डगमागाहट के बावजूद, व्यापारिक आंकड़े मजबूत बने हुए हैं। रोसो ने कहा कि आयात और निर्यात दोनों में साल-दर-साल बढ़ोतरी दिख रही है। 2025 के व्यापार आंकड़ों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर उच्च सिंगल-डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि, उन्होंने हाल के महीनों में भारतीय निर्यात में आई गिरावट की ओर भी इशारा किया। रोसो ने कृषि क्षेत्र को व्यापार समझौते में सबसे बड़ी अड़चन बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के बुनियादी कृषि उत्पादों तक पहुंच की मांग कर रहे हैं। यह भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि देश में बड़ी संख्या में किसान हैं, जिनके पास वैकल्पिक रोजगार के सीमित अवसर हैं। ऐसे में बड़े स्तर पर उदारीकरण सामाजिक और राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। भारत के पक्ष का समर्थन करते हुए रोसो ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था असमान है। जहां एक ओर सेवा क्षेत्र काफी उत्पादक है, वहीं कृषि क्षेत्र की उत्पादकता कम है। उन्होंने कहा कि सुधार धीरे-धीरे और संतुलित तरीके से होने चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी पर अचानक नकारात्मक असर न पड़े। निवेश के

मोर्चे पर रोसो ने भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में अमेरिका की अरबों डॉलर की प्रतिबद्धताओं को दीर्घकालिक सोच का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी और भारत उनमें से एक होगा। उनके अनुमान के मुताबिक, भारत मध्य सदी तक 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है और अमेरिका व चीन को सीधी चुनौती देगा।

सुधारों की बात करें तो रोसो ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत धीमी रही, लेकिन हाल के महीनों में रफ्तार बढ़ी है। उन्होंने जीएसटी में बदलाव और बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति जैसे कदमों का जिक्र किया। 2026 की शुरुआत को लेकर रोसो ने कहा कि साल की पहली तिमाही बेहद अहम होगी। संभावित व्यापार समझौता, अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा, क्वाड नेताओं की बैठक और फरवरी में होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं। साथ ही, भारत में होने वाले राज्य चुनाव भी सुधारों की गति को प्रभावित करेंगे। रोसो ने कहा कि पिछले 11 से 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा के मोर्चे पर खुद को काफी मजबूत किया है और अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग भी गहरा हुआ है।

सुरक्षा उपायों के साथ चिकित्सीय आत्महत्या को मंजूरी, गवर्नर बोलीं- कुछ नियमों के साथ वैध बनाएंगे



न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क में सुरक्षा उपायों के साथ चिकित्सीय आत्महत्या को मंजूरी मिलने जा रही है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होसुलु ने बताया कि डॉक्टरों की देखरेख में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को चिकित्सीय आत्महत्या करने को कानूनी वैधता देने पर सहमत बन गई है। अगले साल इस कानून पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। अगले साल हस्ताक्षर के साथ बन जाएगा कानून : गवर्नर ने कहा, ‘न्यूयॉर्क ‘सुरक्षा उपायों’ के साथ मेडिकल सहायता से आत्महत्या को कानूनी बनाना जा रहा है। बुधवार को गवर्नर और राज्य के कानूनी जानकारों के बीच हुए एक समझौते के तहत, न्यूयॉर्क गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए मेडिकल सहायता से आत्महत्या को कानूनी बनाने वाला राज्य बनने जा रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नर कैथी

होसुलु ने बताया कि वह बिल में कई सुरक्षा उपायों को जोड़ने पर जोर देने के बाद अगले साल इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रही है। अमेरिका में करीब एक दर्जन राज्यों में मेडिकल सहायता से आत्महत्या को अनुमति देने वाले कानून हैं। हाल ही में इलिनोइस राज्य में भी हाल ही में ऐसा कानून बना है, जिस पर अगले साल हस्ताक्षर होंगे। न्यूयॉर्क के मेडिकल एंड इन डाइंग एक्ट के लिए यह जरूरी है कि एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, जिसके

इमरान खान की बहनों और समर्थकों को प्रदर्शन करना पड़ा भारी, आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज



इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान पुलिस ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों और उनके दर्जनों समर्थकों के खिलाफ अडियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। इमरान खान की बहनों और उनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। दरअसल, अधिकारियों ने जेल में बंद नेता के रिश्तेदारों और वकीलों को उनसे मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस के अनुसार, खान की दो बहनों अलीमा खान और नोरीन नियाजी के साथ-साथ सलमान अकरम राजा, नईम पंजोथा, कासिम खान, आलिया हमजा, राजा नासिर अब्बास नाम के पार्टी के नेताओं और समर्थकों के खिलाफ रावलपिंडी के सदर बेरोनी पुलिस स्टेशन में आतंकवाद विरोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एकआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कथित तौर पर राज्य के खिलाफ आपराधिक

साजिश रचने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 120 भी लगाई। पुलिस के मुताबिक कल रात मौके पर ही कम से कम 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। एकआईआर में उल्लिखित अपराधों में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ अप्रैल 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से कई मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने खान से मुलाकातों पर बिना पूर्व सूचना के प्रतिबंध लगा दिए हैं। पुलिस का कहना है कि इस बहाने से कि आगतुक ऐसी मुलाकातों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। खान से आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का याना मामलों के विरोधी पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में स्थिति पर चिंता जताई और पाकिस्तान सरकार से कहा कि वह तत्काल और प्रभावी कदम उठाए।

वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध पर अड़े ट्रंप, सैन्य कार्रवाई रोकने की अमेरिकी संसद की कोशिश भी बेकार



वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला की वेराबंदी बढ़ा दी है, जिसके बाद वेनेजुएला ने अमेरिका पर युद्ध थोपने का आरोप लगाया। बुधवार को कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप की सैन्य कार्रवाई को रोकने की मांग की गई थी, लेकिन सदन के रिपब्लिकन सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जिसके बाद यह खारिज हो गया। डेमोक्रेट्स के समर्थन वाला प्रस्ताव खारिज ट्रंप ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की खिलाफ कार्रवाई बढ़ा दी है। जिस पर कांग्रेस में भी सवाल उठाया। अमेरिकी सेना कैसे एक अभियान चला रही है, जिसके तहत जेनेरल नेत्रो पेरैरा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया दवाओं में इस्तेमाल होने वाले लगभग 90 प्रतिशत एपीआई चीन में बनते हैं। वहीं, अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली शीप 100 जेनेरिक दवाओं में से 83 प्रतिशत एपीआई का कोई भी स्रोत अमेरिका में नहीं है। भारत की भूमिका भी इस आपूर्ति शृंखला में अहम है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग 50 प्रतिशत जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं, लेकिन भारतीय कंपनियां भी अपने लगभग 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक नंबर निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ खेलने’ के लिए मजबूर नहीं किया जा चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग है। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला है। फंडरल बायर मार्केट बनाया, दवा आपूर्ति शृंखला की मॉनिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच नंबर 80 प्रतिशत एपीआई के लिए एक निर्धार है। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर ‘जुआ



अब ब्रॉडर ऑडियंस के लिए फिल्में कर रहा हूँ

आयुष्मान खुयाना इस साल फिल्म थामा में दिखे। उनकी यह फिल्म सुपरहिट रही और उनका मानना है कि यह सफर उनके लिए एक्सपेरिमेंट से भरा रहा है।

क्या अब सिर्फ कमर्शियल फिल्मों की तरफ बढ़ रहे हैं?

मुझे लगता है कि मैं कमर्शियल और एक्सपेरिमेंटल दोनों तरह की फिल्मों में काम करता हूँ। ड्रीम गर्ल मेरे लिए कमर्शियल थी, वहीं थामा भी मेरे लिए कमर्शियल फिल्म साबित हुई है। आगे पति, पत्नी और वो 2 और सूरज बड़जात्या की फिल्म भी बहुत कमर्शियल वैल्यू वाली हैं। इसके बीच में मेरे पास ऐसी कहानियाँ भी हैं जो थोड़ी-सी टेढ़ी हैं या कहें हटके हैं। कमर्शियल सिनेमा का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे पहले बधाई हो और अंधाधुन जैसी हिट फिल्मों का फायदा आर्टिकल 15 जैसी अलग फिल्म को हुआ था, वैसे ही अब ये बड़ी फिल्में उन टेढ़ी फिल्मों को लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगी।

हॉरर-कॉमेडी जॉनर को कैसे देखते हैं?

मुझे लगता है कि हॉरर-कॉमेडी को अब बहुत अच्छा दर्जा दिया गया है, खासकर मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स ने। इतनी बैक-टू-बैक फिल्में अच्छे दर्जे की बनाना आसान नहीं है। मैं बचपन में रामसे ब्रदर्स की फिल्में देखता था और इस जॉनर का फैन रहा हूँ। हॉरर-कॉमेडी का यह कॉम्बिनेशन बहुत कमाल का है। इसके लिए हमेशा ऑडियंस रहती है।

इंटरस्टिंग स्टोरी मिले तो मैं आम आदमी की बायोपिक भी कर सकता हूँ

मैं किसी क्रिकेटर और संगीतज्ञ पर भी फिल्म करना चाहूँगा। ये दोनों चीजें मेरे दिल के बहुत करीब हैं। यहां तक कि अगर कोई इंटरस्टिंग स्टोरी मिले तो मैं आम आदमी की बायोपिक भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे अलग होगी। बाकी आगे मैं सूरज बड़जात्या की एक पारिवारिक फिल्म कर रहा हूँ। उसे लेकर बहुत एक्साइटड हूँ।



अर्जुन रामपाल ने इस काम को बताया जिंदगी का सबसे मुश्किल रोल

अर्जुन रामपाल फिल्म धुरंधर में बेहतरीन अदाकारी को लेकर सुर्खियों में हैं। इसके अलावा वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने गाँबेला डेमेंटियडस से सगाई कर ली है। उन्होंने बताया है कि अपनी पहली पत्नी से तलाक के बाद उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश की है। बेटियों की परवरिश करते हुए

रिश्तों को लेकर उनकी समझ बदली है। धुरंधर एक्टर ने कहा, बच्चों की परवरिश दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। छोटी-छोटी चीजों के लिए भी उन्हें आपसे चिपके रहना पड़ता है और वे हमेशा आपके आस-पास रहते हैं। आप उनके लिए सब कुछ होते हैं। जब उन्हें अपने छोटे पंख मिलते हैं और वे आपके घोंसले से बाहर उड़ना शुरू करते हैं, तब आप

अरशद वारसी ने किया 'असुर 3' का एलान

अभिनेता अरशद वारसी ने हरियाणा में एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेता ने सिनेमा और अपने करियर को लेकर बात की। बातचीत के दौरान अभिनेता ने अपनी लोकप्रिय सीरीज असुर को लेकर भी बड़ी अपडेट साझा की। कार्यक्रम के दौरान जब अरशद वारसी से उनके लोकप्रिय शो 'असुर' को लेकर सवाल किया गया, तो एक्टर ने इसके बारे में बड़ी अपडेट साझा की। एक्टर ने बताया कि वो जल्द ही सीजन 3 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। अरशद ने कहा कि यह बहुत ही मुश्किल रिस्क है लिखने में भी और एक्टिंग के लिहाज से भी। ये साइंस और माथेथोलाजी का ऐसा मिश्रण है, जिसमें आप कहीं भी न तो चूक सकते हैं और न ही लोगों से झूठ बोल सकते हैं। हम इसमें कोई भी मगनदंत बातें नहीं कर सकते। अरशद वारसी ने ये साफ कर दिया है कि सीजन 3 बन रहा है और वो जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू करेंगे।



रजनीकांत की फिल्म से तमन्ना भाटिया का कटा पत्ता

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल पर काम कर रहे हैं। यूं तो इस साल उनकी 'कुली' रिलीज हुई है, जिसे लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया था, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी कमाई की है, पर जैसा काम लोग लोकेश कनगराज से देखना चाहते थे, वैसा दिखाई नहीं दिया। अब रजनीकांत की फिल्म में एक एक्टर की एंट्री हुई है, जिसने तमन्ना भाटिया का पता काट दिया। इस साल साउथ और बॉलीवुड की कई फिल्मों ने सिनेमाघरों में दस्तक दी, कुछ बुरी तरह से पलंग हो गईं, तो कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का कारोबार किया है। अब इंतजार है अगले साल का, जब कई यंग एक्टरों की फिल्में रिलीज की जाएंगी, जबकि, रजनीकांत की एक बड़ी फिल्म भी आ रही है, जिसमें कुछ बॉलीवुड स्टार्स दिखाई देंगे।

हाल ही में पता लगा था कि फिल्म में विद्या बालन की एंट्री कंफर्म है, साथ ही पिक्चर अगले साल यानी 2026 अगस्त तक आ सकती है। लेकिन अब नई एंट्री ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि इस एक्टर से तमन्ना भाटिया का पता काटा है, रजनीकांत जल्द ही कमल हासन के साथ काम करने जा रहे हैं, फिल्म जब अनाउंस हुई थी, जब डायरेक्टर कंफर्म था, लेकिन बाद में फिल्म से डायरेक्टर ने हाथ पीछे खींच लिए, अभी नए डायरेक्टर की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोरा इस गाने के लिए रजनीकांत के साथ 8 दिनों तक शूटिंग कर रही हैं, यूं तो नोरा फतेही लगातार कई म्यूजिक वीडियोज का हिस्सा रह चुकी हैं, साथ ही उनमें भी धमाल मचाती नजर आ जाती हैं, एक बार फिर उसी अंदाज में दिखाई देने वाली हैं, कहा जा रहा है कि 'जेलर 2' का ये गाना नोरा के ब्लॉकबस्टर सॉन्ग की लिस्ट में एंट्री ले सकता है।



त्रिधा चौधरी ने वेब सीरीज आश्रम सीजन 4 पर दिया बड़ा अपडेट

प्रकाश झा की क्राइम ड्रामा सीरीज आश्रम का चौथा सीजन, जिसमें बाँबी देओल लीड रोल में हैं, अगले साल प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। इस शो से नेशनल लेवल पर फेमस होने वाली एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी ने सीरीज के नए सीजन को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया है और बताया है कि ये कब फ्लोर पर आएगी। त्रिधा चौधरी ने शो के बारे में स्पष्ट जानकारी दी। उन्होंने कहा, जी हाँ, हम बहुत जल्द, 2026 में शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। जिससे यह पुष्टि हो गई कि आश्रम 4 पर काम आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला है।

आश्रम सीजन 4 पर अपडेट

बातचीत के दौरान, एक्टर ने यह भी बताया कि कैसे वह इस सीरीज का हिस्सा बनीं और एक मुलाकात का किस्सा सुनाया जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, आश्रम में काम मिलने की कहानी बहुत दिलचस्प है। मैं एक सुपरमार्केट में थी जहाँ मेरी मुलाकात डीए माधवी भट्ट से हुई। उन्होंने मुझसे कहा, 'त्रिधा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे यहाँ मिली। मुझे सच में लगता है कि तुम्हें यह शो करना चाहिए'।

त्रिधा को कैसे मिला रोल!

त्रिधा ने बताया कि लेखिका माधवी भट्ट ने फिल्ममेकर प्रकाश झा को उन्हें इस रोल के लिए चुनने के लिए राजी किया, हालांकि कास्टिंग के साथ कुछ शर्तें भी थीं। उन्होंने बताया, माधवी ने प्रकाश झा सर को मुझे लेने के लिए राजी किया। सर ने कहा, 'नहीं, वो थोड़ी बच्ची लगेंगी।

हमें उसे एक महिला के रूप में दिखाना होगा', इसलिए, मैंने वजन बढ़ाया क्योंकि उन्होंने सलाह दी थी, 'तुम किरदार के लिए इतनी परफेक्ट नहीं दिख सकती। तुम्हें अनुभवी दिखना होगा'। हमारे पास ट्रेनर थे और हमने डायलॉग्स पर भी काफी काम किया। सीरीज को याद करते हुए, त्रिधा ने कहा कि उन्होंने इसकी इतनी बड़ी सफलता की कल्पना कभी नहीं की थी। एक्टर बोलीं, मुझे यकीन करना बहुत मुश्किल था कि इस प्रोजेक्ट से मैं भारत में घर-घर में मशहूर हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा हो गया है।

त्रिधा की किस किसको प्यार करूँ 2

इस बीच, त्रिधा हाल ही में किस किसको प्यार करूँ 2 में नजर आईं, जो 12 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कपिल शर्मा की इस कॉमेडी फिल्म को रिलीज के बाद आलोचकों और दर्शकों से मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं।



मिस इंडिया बनने के बाद भी एक्ट्रेस बनने का सफर आसान नहीं था

एक्टर वार्तिका सिंह ने मॉडलिंग और मिस इंडिया प्रतियोगिताओं के जर्निए अपने अगिनय की राह शुरू की। कई ऑडिशन देने के बाद 'हक' फिल्म में काम करने का मौका मिला। इनका सफर थोड़ा और यानी गौतम जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करके उन्हें प्रेरणा मिली। हाल ही में बातचीत के दौरान वार्तिका सिंह ने बताया कि मिस इंडिया बनने के बाद भी एक्टर बनने का सफर आसान नहीं था।

फिल्म 'हक' में काम करने का मौका कैसे मिला था?

फिल्म हक में काम करने का मौका मुझे कई बार ऑडिशन देने के बाद मिला। शुरुआत में ऑडिशन देने का मन नहीं था, क्योंकि पहले ही कई बार ऑडिशन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। फिर भी कोशिश की, और मेरे लिए रास्ते खुल गए। डायरेक्टर से मिलने पर उन्होंने तुरंत कहा कि मैंने सही सायरा ढूँढ ली है, क्योंकि क्योंकि मेरी दिमाग में सायरा की जो छवि थी उसी के हिसाब से तैयार होकर गई थी।

मिस इंडिया बनने के बाद एक्टर बनने में क्या मुश्किलें आईं?

मॉडलिंग और एक्टिंग अलग होती हैं। मॉडलिंग में दिखना अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक्टिंग में किरदार निभाने की कला और लुक दोनों जरूरी होते हैं। किस्मत और सही समय भी बहुत मायने रखता है। कई बार अच्छे ऑडिशन मिलने के बाद भी किसी और को चुना जाता है क्योंकि मेरा नाम बहुत बड़ा नहीं था। ऐसा मेरे साथ कई बड़े वेब सीरीज में हुआ।

फिल्म साली मोहब्बत मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर की

जी 5 पर आने वाली फिल्म साली मोहब्बत को लेकर दिव्येंद्र शर्मा खासे उत्साहित हैं। इसमें वह रतन पंडित नामक एक कॉप बनने हैं। इस फिल्म समेत उनसे अन्य प्रोजेक्ट्स पर हुई खास बातचीत...

साली मोहब्बत का ऑफर आपको कैसे मिला?

यह फिल्म मेरे पास दबे पांव से, बिल्कुल खुसुर-खुसुर करते हुए आई थी। दरअसल इसकी चर्चा काफी समय से चल रही थी लेकिन जब टिस्का चोपड़ा ने पहली बार मुझसे संपर्क किया तो डेट्स की उपलब्धता न होने के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई। सीधी बात ये थी कि टाइम विंडो मैच नहीं कर पाई। बहरहाल, उसके लगभग आठ-नौ महीने बाद इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू हुआ। इस बार जब हम मिले और मैंने रिस्क

पढ़ी तो मुझे वाकई में बहुत मजा आया। रिस्क पढ़ने के बाद मैं फिर से टिस्का से मिला और तब तक फैशन की दुनिया के बड़े नाम मनीष मल्होत्रा भी एक निर्माता के तौर पर इस फिल्म से जुड़ चुके थे। इस तरह इस प्रोजेक्ट की बात दोबारा शुरू हुई और वहीं से पूरा प्रोसेस आगे बढ़ा। मेरे लिए यह फिल्म एक तरह से किस्मत का फेर थी जो घुसकर मेरे पास आई।

यह मर्डर मिस्ट्री आपको बाकी कहानियों से अलग कैसे लगी?

मैं हमेशा कहता हूँ कि इस रिस्क में एक अलग सी खुशबू थी, जो मुझे बहुत पसंद आई। इसमें जो बातें थीं, वो कुछ अनकही सी थीं, कुछ धुंधली-सी थीं, यानी सब कुछ स्पष्ट नहीं था। यह फ्लेवर मुझे खींच लाया। यह मर्डर मिस्ट्री है लेकिन यहां जो किरदार इस कहानी में घूम रहे हैं, उनकी सिचुएशन बहुत ही जटिल है। कोई भी किरदार न तो

पूरी तरह ब्लैक है और न ही पूरी तरह व्हाइट। यहां अलग शेड्स हैं, जो कहानी को विश्वसनीय बनाते हैं। साथ ही मुझे एक पुलिस वाले का किरदार निभाने का मौका मिला था। इन सब चीजों को मिलाकर मुझे लगा कि यह एक शानदार प्रोजेक्ट है। इमानदारी से कहूँ तो, मैंने यह फिल्म एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर की, यह देखने के लिए कि फिल्म का नैरेटिव किस तरह से आगे बढ़ेगा, और मैं अपने रतन पंडित के किरदार को किस हद तक जस्टिफाई कर पाऊँगा।

राधिका के साथ काम करने का अनुभव कैसा था?

राधिका आटे के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। हमारे बहुत अधिक सीन तो साथ में नहीं थे, क्योंकि हमारे ट्रैक्स ज्यादातर पैरेलल को-एक्टर साबित हुईं।

क्या फीमेल डायरेक्टर वॉयलेंस को कम ग्लोरीफाई करती हैं?

एक फीमेल डायरेक्टर का वॉयलेंस को देखने का तरीका अलग होता है। मेल डायरेक्टरों का वॉयलेंस दिखाने का तरीका सामने से आकर लड़ाई-झगड़ा करना होता है लेकिन टिस्का चोपड़ा जैसी डायरेक्टर के साथ यह मुझे बिल्कुल अंडर दी टेबल जैसी लगी। हालांकि, मैं यह साफ कर दूँ कि उनकी अप्रोच अलग थी पर फिल्म वॉयलेंस उतनी ही है।



इंडियन कोस्टगार्ड-असम राइफल्स एजुकेशनल एक्सचेंज ने दमण में इंटर सर्विस तालिमेल को मजबूत किया



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। इंटर-सर्विस तालिमेल और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण को मजबूत करने के मकसद से इंडियन कोस्टगार्ड-असम राइफल्स के जुड़ाव के तहत, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल के 15 छात्रों और 04 स्टाफ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 14 से 19 दिसंबर 2025 तक एक एजुकेशनल टूर के लिए कोस्टगार्ड पब्लिक स्कूल दमण गया। इस टूर का मकसद छात्रों को इंडियन कोस्टगार्ड की भूमिका और मिशन के बारे में सीधे अनुभव देना था। दमण यात्रा के दौरान, छात्रों ने दमण और सिलवासा में महत्वपूर्ण जगहों का दौरा किया। जिससे उन्हें दमण की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अहमियत के बारे में जानकारी मिली। एजुकेशनल और अनुभव आधारित सीखने के हिस्से के तौर पर छात्रों के लिए एक होवरक्राफ्ट सॉर्टी का आयोजन किया गया, जिससे उन्हें होवरक्राफ्ट ऑपरेशन और तटीय निगरानी और (समाचार का शेष पेज 3 पर)

दमण-दीव के 65वें मुक्ति दिवस पर भारतीय तटरक्षक बल जिला मुख्यालय ने दीव में किया ऑपरेशनल डेमो



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। भारतीय तटरक्षक बल जिला मुख्यालय संख्या 1 (दक्षिण गुजरात, दमण और दीव) ने दीव में एक प्रशासन के सहयोग से 19 दिसंबर 2025 को दमण-दीव मुक्ति दिवस के अवसर पर घोधला बीच, दीव में एक ऑपरेशनल डेमो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के समुद्री हितों की रक्षा में भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन क्षमताओं और बहु-मिशन तत्परता का प्रदर्शन करना था। डेमो के दौरान, भारतीय तटरक्षक बल के हेलीकॉप्टर और रिमोट कंट्रोल जीवन रक्षक वलय द्वारा खोज और बचाव अभ्यास (समाचार का शेष पेज 3 पर)

सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का हुआ आयोजन



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, सिलवासा 19 दिसंबर। जिला प्रशासन द्वारा जनसुविधा एवं जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सुशासन सप्ताह के तहत 19/12/2025 को सुबह 10.00 बजे से ग्राम पंचायत दादरा, देमणी, गलौंडा, उमरकुई, किलवणी एवं राधा में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को उनके निवास स्थान के निकट ही विभिन्न शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे, जिनमें राजस्व, पंचायत, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, श्रम एवं अन्य संबंधित विभाग शामिल थे। नागरिकों से संबंधित आवेदन, शिकायतें एवं मांगें प्राप्त की गईं (समाचार का शेष पेज 3 पर)

ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए रखोली, कराड एवं सायली में ग्रामसभा का आयोजन



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, सिलवासा 19 दिसंबर। ग्राम पंचायत के सर्वांगीण एवं सहभागी विकास के उद्देश्य से जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) के अंतर्गत 19/12/2025 को सुबह 11.00 बजे ग्राम पंचायत रखोली एवं कराड में और दोपहर 3.00 बजे ग्राम पंचायत सायली में ग्रामसभा का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस ग्रामसभा का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर विकास संबंधी आवश्यकताओं की पहचान कर प्राथमिकताओं के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना तैयार करना रहा। ग्रामसभा में सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत सचिव, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों की वीदियाँ, आंगणवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, युवा वर्ग एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, आवास, आजीविका, कृषि, महिला एवं बाल विकास तथा (समाचार का शेष पेज 3 पर)

सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी ने डीआईसी और डीआईए के साथ मिलकर किया जागरूकता कार्यक्रम

■ सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम से 200 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को हुआ फायदा



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी ने डीआईसी और दमण इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ मिलकर 18 दिसंबर 2025 को सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी नियमों पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिससे दमण और सिलवासा की 200 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ। यह प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के सपोर्ट से ऑर्गनाइज किया गया था, जिसका मकसद सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी गाइडलाइंस, एनओसी लेने के प्रोसेस, कम्प्लायंस की जरूरतों और Ease of Doing Business पहल के तहत ग्राउंडवॉटर मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाना था। अलग-अलग इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने सेशन में एक्टिवली हिस्सा लिया और सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी अधिकारियों और एक्सपर्ट्स से प्रैक्टिकल गाइडेंस ली। इंटरैक्टिव डिस्कशन और हेल्प-डेस्क सपोर्ट से पार्टिसिपेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन और रेगुलेटरी कम्प्लायंस से जुड़े अपने सवालों को क्लियर करने में मदद मिली। इस पहल की इंडस्ट्रियल कम्युनिटी ने बहुत तारीफ की, क्योंकि इससे इंडस्ट्रीज को बेहतर कम्प्लायंस, सस्टेनेबल ग्राउंडवॉटर इस्तेमाल और आसान रेगुलेटरी प्रोसेस पक्का करने में मदद मिलेगी। इंडस्ट्रीज ऑर्गनाइजर ने प्रोग्राम को सफल बनाने में उनके सहयोग और सपोर्ट के लिए डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी अधिकारियों और दमण इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का दिल से शुक्रिया अदा किया। इस कार्यक्रम में डीआईए प्रेसिडेंट पवन अग्रवाल, विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

दिलीपनगर डेवलपमेंट एसोसिएशन ने मनाया दमण-दीव का 65वां मुक्ति दिवस: वैशाली भट्ट ने किया ध्वजारोहण



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। दिलीपनगर डेवलपमेंट एसोसिएशन ने हार्थोल्लास के साथ दमण-दीव का 65वां मुक्ति दिवस मनाया। डीडीए की दिलीपनगर महिला मंडल की अध्यक्ष वैशाली भट्ट ने को सलामी दी और स्वतंत्रता हाथों तिरंगा फहराया गया। इस सेनानियों को नमन किया। डेवलपमेंट एसोसिएशन ने मौके पर उपस्थित सभी ने तिरंगे (समाचार का शेष पेज 3 पर)

दमण-दीव के मुक्ति दिवस पर कचीगाम सरपंच फाल्गुनी पटेल ने पंचायत घर पर फहराया तिरंगा



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। दमण-दीव के 65वें मुक्ति दिवस पर कचीगाम ग्राम पंचायत की सरपंच फाल्गुनी पटेल ने कचीगाम पंचायत घर पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर पंचायत सदस्यों, स्कूली बच्चों एवं नागरिकों की उपस्थिति रही।

दमण-दीव के लिबरेशन-डे पर दुनेठा सरपंच आशा पटेल ने तिरंगे को दी सलामी



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। दमण-दीव के 65वें लिबरेशन-डे पर दुनेठा ग्राम पंचायत सरपंच आशा संजय पटेल ने पंचायत घर पर तिरंगा लहराया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों एवं पंचायत सदस्यों एवं नागरिकों की उपस्थिति रही।

कडैया ग्राम पंचायत सरपंच शंकर पटेल ने ग्रामजनों के साथ मनाया दमण-दीव का 65वां मुक्ति दिवस



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। दमण-दीव के 65वें मुक्ति दिवस पर कडैया ग्राम पंचायत सरपंच शंकर पटेल ने पंचायत घर पर ग्रामजनों की उपस्थिति में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर कडैया जिला पंचायत सदस्य हर्षल पटेल, पंचायत सदस्यों की उपस्थिति रही।

डीएमसी काउंसिलर अस्पी दमणिया ने वॉर्ड नं. 6 में आयुष्मान वय वंदना कैप का किया आयोजन



असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 दिसंबर। डीएमसी काउंसिलर अस्पी दमणिया ने वॉर्ड नं. 6 में भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान वय वंदना कैप का आयोजन किया था। इस शिफ्ट के माध्यम से 100 से अधिक नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से देश के नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश आगरिया, सीताराम, पीयूष पटेल, आमिर दमण जिला भाजपा अध्यक्ष भरत मोरे, जसविंदर कौर, दमण जिला पंचायत के सदस्य अशोक पटेल की उपस्थिति रही।